वर्ष-1, अंक-03, फरवरी-2026

R.N.I.No.UPHIN/25/A3973

मूल्य-50/- रूपए

हिन्दी मासिक पत्रिका

खुशी समय

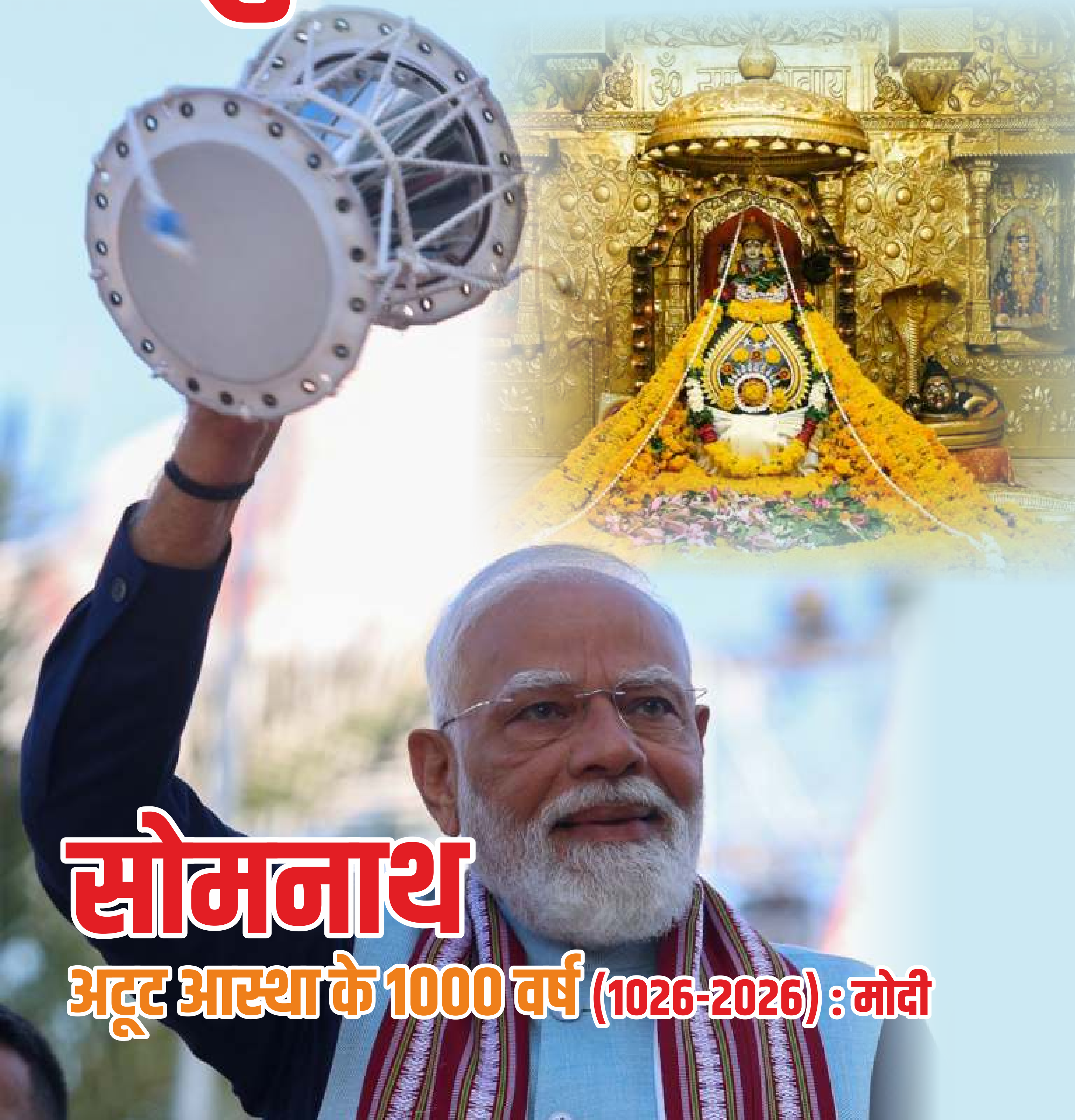

सोमनाथ

अटूट आस्था के 1000 वर्ष (1026-2026) : मोदी

विकसित भारत
विकसित उत्तर प्रदेश

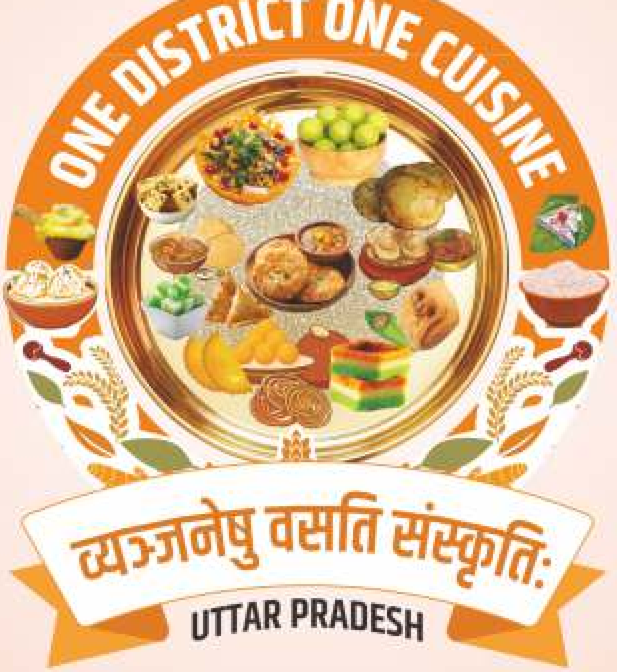

उत्तर प्रदेश दिवस (24 जनवरी, 2026) के अवसर पर

एक जनपद-एक व्यञ्जन योजना लॉन्च

- प्रदेश के हर जनपद के विशिष्ट व्यंञ्जनों को मिलेगी नई पहचान
- पारंपरिक कारीगरों, हलवाइयों, छोटे उद्यमियों को स्थायी आजीविका के अवसर

प्रगति की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

R.N.I.No.UPHIN/25/A3973

खुशी समय

हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:01 अंक:03 फरवरी-2026

संरक्षक

एस.पी. द्विवेदी

सलाहकार

अरविन्द पाण्डेय

शशिधर द्विवेदी

कार्यकारी सम्पादक

एस. एन. लाल

संपादक

अम्ब्रीश द्विवेदी

कानूनी सलाहकार

अजय श्रीवास्तव, एडवोकेट

ब्यूरो चीफ

प्रभात पाण्डेय

संवाददाता

बसन्त कुमार सिंह	- बलिया
ऋचा	- बाराबंकी
रवि प्रताप सिंह	- गोरखपुर
संतोष गुप्ता	- दिल्ली
गौरव शुक्ला	- गोण्डा
रमेश कुमार	- प्रयागराज

स्वामी, प्रकाशक व सम्पादक अम्ब्रीश द्विवेदी ने मुद्रक सुरेश कश्यप, प्लाट संख्या-38, गाटा संख्या 99, ग्राम कपासी, लखनऊ उ.प्र. से मुद्रित करवा कर सी-695, निकट अरावली मार्ग, सेकटर-6, इन्दिरानगर, लखनऊ उ.प्र. से प्रकाशित किया।

मो0: 8090111100

सम्पादक अम्ब्रीश द्विवेदी

पत्रिका के सभी पद अवैतनिक है। प्रकाशित लेख, समाचार, विचार व आंकड़े रचनाकारों के हैं। उन विचारों से सहमत होना संपादक के लिए आवश्यक नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय स्थल लखनऊ होगा।

इस अंक में

16

सोमनाथ अटूट आस्था के 1000 वर्ष...

05

कितना जरूरी था ईयू के कार्बन टैक्स से छूट मिलना?

06

यूपी की कानून-व्यवस्था अपने में एक मिसाल

32

जोश से भरी टीम...

SIR के बीच सुप्रीम कोर्ट की एंट्री

निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के संदर्भ में एक सबसे अहम अपेक्षा यह रही है कि इसे पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। कई तरह के विवादों के बीच विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई एक प्रमुख मांग भी यही है। इस मसले पर निर्वाचन आयोग की यही दलील रही है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य अपात्र लोगों को बाहर करना है। इसमें स्थान बदलने वाले लोगों से लेकर वैसे लोग भी शामिल होंगे, जिनकी मौत हो चुकी है।

इस घोषित मकसद से किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची से जितनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम बाहर होने की खबरें आई हैं, उसे लेकर कई सवाल उठे हैं। इसकी जड़ में मुख्य कारण इस समूची प्रक्रिया में अपेक्षित पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं किया जाना हो सकता है और इसीलिए आम नागरिकों के बीच तमाम आशंकाएं उभरीं। अगर एसआइआर की प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक पूरी तरह पारदर्शी बनाने की व्यवस्था की जाती, तो संभवत: अनावश्यक विवाद नहीं खड़े होते।

अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस समूची कवायद में तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में रखे गए मतदाताओं का सत्यापन पूरी तरह पारदर्शी ढंग से हो और इससे लोगों को अनावश्यक तनाव तथा असुविधा न हो। गौरतलब है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान ऐसी तमाम शिकायतें सामने आईं कि मनमाने तरीके से नागरिकों के नाम बाहर किए गए। कई जगहों पर लोगों को समय पर इसकी जानकारी भी नहीं हुई और उनका नाम मतदाता सूची से हट गया। जाहिर है, निर्वाचन आयोग की ओर से यह प्रक्रिया जिस स्तर पर चलाई गई, उसमें मतदाता सूची से बाहर होने वाले लोगों को सूचित करने और उन्हें अवसर देने को लेकर सवाल उठे।

पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम, उपनाम, आयु में गड़बड़ी आदि की वजह से करीब एक करोड़ पच्चीस लाख मतदाताओं को तार्किक विसंगति नोटिस जारी किया था। इस संदर्भ में शीर्ष अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह किसी भी तरह की गड़बड़ी वाली मतदाता सूची को ग्राम पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय और वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक तौर पर लगाए, ताकि लोगों को पता चल सके।

सवाल है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का जो काम निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रिया में प्राथमिक स्तर पर खुद ही अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तार्किक विसंगति के दायरे में आए सभी नामों को सार्वजनिक करने के अलावा मतदाता सूची में नाम होने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था।

सच यह है कि बिहार सहित देश के जिन राज्यों में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया संचालित की गई, वहां सबसे अहम सवाल पारदर्शिता को लेकर ही उठे। इससे किसी को भी असहमति नहीं होगी कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी अवैध रूप से हिस्सा न ले और सिर्फ पात्र लोगों को ही मतदान का अधिकार मिले। मगर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सभी पात्र लोगों को खुद को सही साबित करने के लिए जरूरी अवसर और सुविधा मिले, ताकि वह मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न हो। ■

सम्पादक

कितना जरूरी था ईयू के कार्बन टैक्स से छूट मिलना?

भारत ने यूरोपीय यूनियन से साथ ट्रेड डील के निगोशिएशन में भारतीय व्यापार के लिए कॉर्बन बॉर्डर एडस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) में तेजी से सबसे पंसदीदा देश की सूची (एमएफएन) में खुद को शामिल कर लिया। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस कदम से भारतीय उद्योग को वही छूट मिलेंगी, जो यूरोपीय यूनियन ने पिछले साल ट्रेड डील समझौते के तहत अमेरिका को देने का वादा किया था।

पिछले साल अगस्त 2025 में जारी यूरोपीय यूनियन-अमेरिका व्यापार समझौते के संयुक्त बयान में ईयू ने कहा था, "सीबीएएम के तहत अमेरिका के लघु और मध्यम आकार के बिजनेस के साथ ईयू न्यूनतम अपवाद में वृद्धि के अलावा सीबीएएम कार्यान्वयन में अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

पहले नहीं था ये डील का हिस्सा: इंडियन एक्सप्रेस ने अगस्त 2025 में रिपोर्ट किया था कि भारतीय बातचीत करने वाले अगले महीने ब्रसेल्स में होने वाली बातचीत के अगले दौर में इसी तरह की राहत के लिए जोर देने की योजना बना रहे हैं। US-EU डील से पहले, ईयू अधिकारियों ने कहा था कि CBAM कोई ट्रेड मेजर नहीं है। ईयू में भारत के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने जून में इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, "यह ट्रेड और FTA (भारत के साथ) का हिस्सा नहीं है। यह डीकार्बनाइज़ेशन को तेज करने के लिए हमारे क्लाइमेट एजेंडा के पालन के बारे में है।"

कार्बन टैक्स पर क्या थी शिकायतें? कार्बन टैक्स के तहत जनवरी 2026 से ईयू में इंपोर्ट होने वाले अधिक कार्बन वाले सामानों पर टैक्स लग रहे हैं। कई विकासशील देश इसे भेदभावपूर्ण और इंटरनेशनल पर्यावरण कानून के खिलाफ मानते हैं। ब्राज़ील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) के मंचों पर CBAM को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थी और रूस ने पिछले साल 12 मई 2025 को एक औपचारिक विवाद शुरू कर दिया था।

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि भारत ने कम कार्बन वाले स्टील प्रोडक्शन के लिए एक जरूरी इनपुट, स्टील स्क्रैप तक आसान पहुंच की भी मांग की है और इस पर एक सहमति भी बनी है। अधिकारी ने कहा, "हमने EU की रीसाइक्लिंग पॉलिसी के तहत स्क्रैप पाने के लिए अप्लाई किया है। हमारी एक सहमति भी बनी है, लेकिन हमारे पास एक रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म भी है जो हमें अपने हितों को नुकसान पहुंचने पर उन पर बराबर लागत लगाने की इजाजत देता है।"

अधिकारी ने कहा कि CBAM को लेकर बातचीत सबसे मुश्किल रही है क्योंकि ईयू कार्बन टैक्स सभी देशों पर लागू होता है, लेकिन भारत और ईयू के बीच एक समझ बनी है जिसके तहत दोनों ट्रेड पार्टनर डीकार्बनाइजेशन की दिशा में मिलकर काम करेंगे, और ईयू इसके लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करने पर राजी हो गया है।

स्टील का था बड़ा मुद्दा: भारतीय ट्रेड नेगोशिएटर्स ने ट्रेड डील के तहत यूरोपियन यूनियन में बनने वाले स्टील स्क्रैप तक आसान पहुंच की मांग की थी, जिससे ब्लॉक के CBAM के असर को कम किया जा सके।

यह कदम भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की चिंताओं के बाद उठाया गया है कि CBAM, ईयू की रीसाइक्लिंग पॉलिसी के साथ मिलकर एक "नॉन-टैरिफ बैरियर" के रूप में काम करता है, जो न केवल 27 देशों के ब्लॉक में मेटल एक्सपोर्ट को रोकता है, बल्कि घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों को स्क्रैप एक्सपोर्ट को भी सीमित करता है। बता दें कि ईयू दुनिया में स्टील स्क्रैप का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने 25 नवंबर को बोर्ड ऑफ ट्रेड (BoT) की मीटिंग के दौरान बताया, "भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के मुद्दे पर, ईयू के CBAM उपायों के लिए स्टील स्क्रैप की सोर्सिंग के साथ आर्क फर्नेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी होगा। हालांकि, ईयू की रीसाइक्लिंग पॉलिसी के कारण वहां से स्क्रैप सोर्स करना मुश्किल था, और इसलिए यह एक नॉन-टैरिफ बैरियर होगा।" स्टील प्रोडक्शन से होने वाला धुएं आमतौर पर ब्लास्ट फर्नेस-बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (BF-BOF) रूट्स के लिए सबसे अधिक होता है, गैस-बेस्ड डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) के लिए कम और स्क्रैप-बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) रूट्स के लिए सबसे कम होता है। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अधिकतर ब्लास्ट फर्नेस रूट का इस्तेमाल करते हैं और फिलहाल CBAM से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि, सरकार के पास 'ग्रीन स्टील इनिशिएटिव' के तहत आर्क फर्नेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्टील स्क्रैप से स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना है।

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का अनुमान था कि CBAM भारत के आयरन, स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स जैसे मेटल्स के ईयू को होने वाले एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाएगा और ईयू में चुनिंदा इंपोर्ट पर 20-35 प्रतिशत टैक्स लगेगा। ■

यूपी की कानून-व्यवस्था अपने में एक मिसाल

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सरोजनीनगर इण्डस्ट्रियल एरिया में अशोक लेलैण्ड के नवीन मैन्युफैक्चरिंग प्लाण्ट का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तथा भारी उद्योग मंत्री ने अशोक लेलैण्ड के इलेक्ट्रिक वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। प्लाण्ट का अवलोकन किया तथा परिसर में सिन्दूर व रुद्राक्ष का पौधरोपण किया।

रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है। आज यह प्रदेश विकास का पर्याय बन चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को जिस तरह सुदृढ़ किया है, यह अपने में एक मिसाल है। आम जन सरकार से समाज में अमन-चैन बनाए रखने की भी उम्मीद रखता है। एक ऐसा समाज जहां कोई भय न हो। जहाँ लोगों को घर से बाहर निकलने के पहले सोचना न पड़े। जहाँ उद्योगपति उद्योग लगाने में न हिचकें तथा इन्वेस्टर्स निवेश करने में न डरें। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ में वर्ल्ड क्लास ग्रीन फील्ड इण्टीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन सम्पूर्ण प्रदेश के लिए सुखद क्षण है। इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में

> *“लखनऊ में वर्ल्ड क्लास ग्रीन फील्ड इण्टीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन सम्पूर्ण प्रदेश के लिए सुखद क्षण, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी”*

विगत माह राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। यह प्रेरणा स्थल सभी को देखना चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश को किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उसी प्रदेश में नित नये उद्योग स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपना मेजर कन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। इससे बड़ा अचीवमेण्ट इस स्टेट के लिए और क्या हो सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ बनाये गये डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से हथियार, गोला-बारूद और लड़ाकू जहाजों से सम्बन्धित सामान बनेगा। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ यहां अपने कारखाने लगा रही हैं, जिससे गाँव के लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा।

लखनऊ में ब्रह्मोस एयररोस्पेस की फैक्ट्री भी स्थापित की गयी है, जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है। जिसका करिश्मा आप लोगों ने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान देखा होगा। अब यह मिसाइल बाहर से बनकर नहीं आती है। हमारे अपने देश में और अपने उत्तर प्रदेश में ही बनती है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस की फैक्ट्री स्थापित करने में मुख्यमंत्री जी की पहल व सहयोग सराहनीय है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब भारत अपने हथियार खुद बना रहा है। उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने विकास के इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस एण्ड डिफेंस यूनिट एण्ड एम्प्लॉयमेण्ट प्रमोशन’ पॉलिसी बनाई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाया जा रहा है, जहां सेना के लिए साजो-सामान बड़े पैमाने पर बनेंगे। प्रदेश सरकार ‘ग्लोबल-500 एण्ड फॉर्च्यून इण्डिया-

यूपी देश के विकास में मेजर कण्ट्रीब्यूशन दे रहा: सी एम

500 कम्पनी इन्वेस्टमेण्ट प्रमोशन पॉलिसी-2023' भी लेकर आयी है, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेण्ट तथा औद्योगिक विकास बढ़ सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का समारोह प्रदेश के प्रति उद्योगपतियों के बढ़ते हुए विश्वास का प्रतीक है। इस इण्टीग्रेटेड पैसेज एण्ड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लाण्ट में 2,500 यूनिट प्रतिवर्ष की क्षमता है, जिसे चरणबद्ध ढंग से 5,000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता और हम सभी के दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वॉर्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है। विभिन्न प्रकार की आपदाएँ हम सबके सामने एक नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लाण्ट स्वयं को तैयार करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का हिस्सा है। इसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की सम्भावनाएँ विकसित हुई हैं। प्रदेश सरकार पर विश्वास कर लखनऊ में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए हिन्दुजा समूह बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश असीमित सम्भावनाओं का ही नहीं, बल्कि सम्भावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। पिछले साढ़े 8 वर्षों में हुए बड़े परिवर्तन इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज प्रदेश के समस्त जनपदों में भारी पैमाने पर निवेश हो रहा है। यहां बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेस-वे का 55 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे आज उत्तर प्रदेश के पास है। प्रदेश के सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क प्रदेश में है। देश में बनने वाले दो डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रदेश से होकर निकल रहे हैं। इस फ्रेट कॉरीडोर पर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स एण्ड ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में देश की पहली रैपिड रेल और पहला वॉटर-वे संचालित हो चुका है।

> *यह प्लाण्ट 'मेक इन इण्डिया' के साथ प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम अशोक लेलैण्ड के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लाण्ट में प्रदेश के 10,000 युवाओं को प्रतिवर्ष स्किल डेवलपमेण्ट के साथ जोड़ने के लिए हिन्दुजा ग्रुप प्रदेश सरकार के साथ एमओयू करने जा रहा*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि उत्सव का प्रदेश बन चुका है। विगत 5 वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुका है। दृढ़ निश्चय, साफ नीयत से लिए गए फैसलों तथा स्पष्ट सोच से आज फियरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुके हैं। अब यहाँ कोई निवेशक पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं होता। प्रदेश में 34 सेक्टोरियल पॉलिसी हैं, जिनके माध्यम से कोई भी निवेशक विभिन्न सेक्टरों में निवेश कर प्रदेश की विकास यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। विगत लगभग 9 वर्षों में प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए, जिसमें 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग हो चुकी है। लगभग 6 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार हैं, जिनकी आगामी माह ग्राउण्ड ब्रेकिंग की जाएगी। इसके साथ ही, 5 लाख करोड़ रुपये के अन्य प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, जिनकी ग्राउण्ड ब्रेकिंग भी आगामी समय में की जाएगी। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 36 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के साथ वर्ष 2029-30 तक प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55 प्रतिशत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का 60 प्रतिशत प्रदेश में निर्मित हो रहा है। प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में टॉप अचीवर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अशोक लेलैण्ड का यह मैन्युफैक्चरिंग प्लाण्ट प्रदेश के लिए एफडीआई और फॉर्च्यून-500 पॉलिसी का हिस्सा है। वर्ष 2017 से पूर्व एफडीआई में यूपी का अंश बहुत कम था। आज प्रदेश ने अपनी पॉलिसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर एफडीआई और फॉर्च्यून-500 को आकर्षित किया है। इस प्लाण्ट के लिए सितम्बर, 2023 में एमओयू हुआ, जनवरी, 2024 में एलओआई तथा भूमि स्थानान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न हुई। केवल 18 महीनों में एक विश्वस्तरीय प्लाण्ट निर्मित होकर प्रदेश को समर्पित किया जा रहा है। यह डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली और सुशासन का प्रमाण है।■

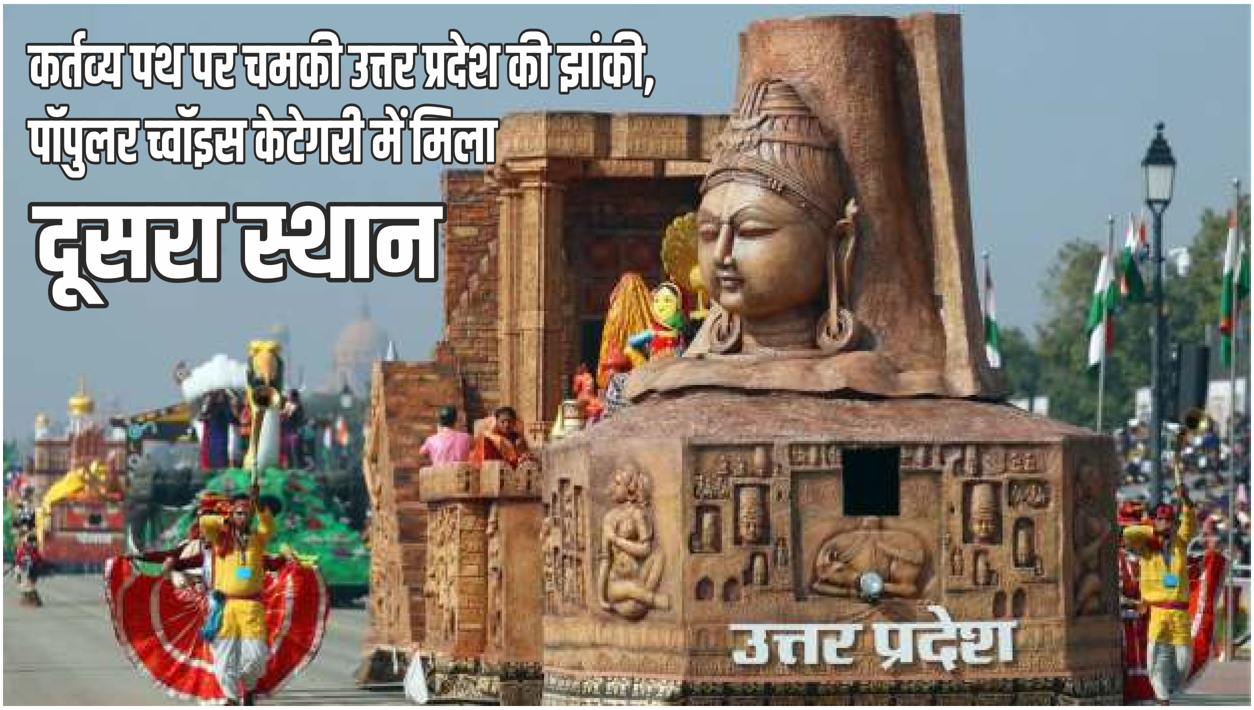

कर्तव्य पथ पर चमकी उत्तर प्रदेश की झांकी, पॉपुलर च्वॉइस केटेगरी में मिला दूसरा स्थान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उन्नति की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस परेड में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में प्रदेश की झांकी को पॉपुलर च्वॉइस केटेगरी में द्वितीय पुरस्कार मिला। लोगों द्वारा सराही गई इस झांकी में बुंदेलखण्ड की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास यात्रा को केन्द्रित किया गया था। उत्तर प्रदेश ने लगातार सातवें वर्ष पुरस्कार प्राप्त कर अपनी विशिष्ट सृजनात्मक पहचान कायम रखी। कुल 30 झांकियों में प्राप्त किया दूसरा स्थाननई दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अपर निदेशक अरविंद कुमार मिश्र को केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 13 मंत्रालयों व विभागों की कुल 30 झांकियां शामिल थीं, जिनमें लोकप्रियता के आधार पर उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला। बुंदेलखण्ड की विरासत और आधुनिक विकास को किया गया प्रदर्शितसमृद्धि का मंत्र-आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित इस झांकी में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखण्ड की संस्कृति के साथ-साथ आधुनिक उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की झलक भी दिखाई थी। झांकी में बुंदेलखण्ड की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को प्रमुखता से दर्शाया गया। कालिंजर दुर्ग की शैल कला और एकमुख लिंग, क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करते दिखाई दिए। झांकी में बुंदेलखंड की मृद्भांड कला, मनका शिल्प, पारंपरिक हस्तशिल्प, एक जनपद एक उत्पाद, ब्रह्मोस मिसाइल, एक्सप्रेस नेटवर्क और आधुनिक अवसंरचना की झलक भी शामिल थी, जिसने विकास और परंपरा का संतुलित चित्र प्रस्तुत किया।सात वर्षों से जारी सम्मान की परंपराउत्तर प्रदेश को आकर्षक झांकी के लिए लगातार सातवें वर्ष सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकियों ने वर्ष 2020 में द्वितीय तथा वर्ष 2021 और 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता। वहीं, वर्ष 2023 में झांकी को ज्यूरी श्रेणी में तृतीय और पॉपुलर च्वॉइस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार, झांकी को वर्ष 2024 में पॉपुलर च्वॉइस श्रेणी में द्वितीय स्थान, वर्ष 2025 में ज्यूरी श्रेणी में प्रथम तथा पॉपुलर च्वॉइस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला। वर्ष 2026 में भी पॉपुलर च्वॉइस श्रेणी में प्रदेश की झांकी दूसरे स्थान पर रही, जिससे राष्ट्रीय मंच पर उत्तर प्रदेश की सृजनात्मक पहचान और मजबूत हुई। ■

संघ प्रमुख : हिन्दुस्थान हिन्दू राष्ट्र है।
सभी हिन्दू सहोदर हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा है कि मन्दिर कुआं और श्मशान सभी हिन्दुओं के लिए खुले होने चाहिए और उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरसंघचालक जी निराला नगर स्थित सरस्वती विद्या मन्दिर के माधव सभागार में "कार्यकर्ता कुटुम्ब मिलन" कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि करियर क्या है? पेट भरना, ज्यादा कमाना, उपभोग करना करियर नहीं है। करियर कमाने से ज्यादा बाँटने में है। बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो अमीर होकर दान दें, दूसरों के लिए जीना सीखें। घरों में ऐसे संस्कार देने होंगे जिनके अनुसार बच्चे यह समझें कि हमारा हित ही देश के साथ है। मेरे लिए मेरा देश ही पहले है। विद्या और धन अपने देश के लिए कमाना चाहिए।सारे हिन्दू समाज को एक मानता है संघसरसंघचालक ने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर प्रयास होने चाहिए। संघ सारे हिन्दू समाज को एक मानता है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर आपसी मेलजोल बढ़ाना चाहिए। सामाजिक समरसता भाषण से नहीं, करने से आएगी। संघ के कुटुम्ब में जात-पात नहीं है। ऐसा ही समाज में करना होगा। सरसंघचालक जी ने कहा कि संघ पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षा स्वयंसेवक को देखने से अधिक समझ में आता है।समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार सरसंघचालक जी ने कहा कि समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। सामाजिक व्यवहार का परीक्षण परिवार में होता है। बचत करना हमारे परिवारों की आदत में है। देश का धन हमारे घरों में रहता है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को मातृभाषा ठीक से आए। हमारे अन्दर देशभक्ति, प्रमाणिकता, अनुशासन और कुटुम्ब गौरव का भाव होना चाहिए। बस्ती और शाखा में हो कुटुम्ब मिलनसरसंघचालक जी ने कहा कि 100 से 70 की संख्या में कुटुम्ब मिलन बस्ती और शाखा स्तर पर होना चाहिए। हमें अभाव में नहीं रहना है लेकिन किसी के प्रभाव में भी नहीं आना है। जैसा संघ है वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। पंच परिवर्तन कार्यक्रमों में मातृशक्ति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्थान हिन्दू राष्ट्र हैसरसंचालक जी ने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि हिन्दुस्थान हिन्दू राष्ट्र है, हम सभी हिन्दू अपने सहोदर हैं। समाज में जो भी वर्ग संघ के निकट नहीं है, संघ कार्यकर्ताओं को उनके निकट जाना चाहिए। उनसे आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध विकसित करने चाहिए। वह सम्बन्ध चौराहे से शुरू होकर कुटुम्ब तक विस्तृत हों। सब अपने हैं, हमें यह मानकर व्यवहार करना है। स्क्रीन का समय निश्चित होसरसंघचालक जी ने कहा कि हम तकनीक को नहीं रोक सकते लेकिन इसका उपयोग अनुशासन में रहकर हो। कितने समय तक क्या देखना है यह निर्धारित होना चाहिए। विज्ञान एआई, टीवी, मोबाइल और फिल्मों की हानियाँ भी बताता है। नई पीढ़ी को यह सब बताना चाहिए।

संघ चिरतरुण संगठनसरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि आज भारतीय ज्ञान परम्परा को सभी जगह माना जाता है। यह विषय हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। तब उन्हें समझ में आएगा कि हम क्या हैं। उन्होंने आगे कहा कि संघ चिरतरुण संगठन है और भारत के सबसे अधिक युवा संघ के पास हैं।■

यूपी बना मजबूत कानून व्यवस्था का उदाहरण

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित 'उत्तर प्रदेश दिवस' के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन का शुभारम्भ तथा 'एक जिला एक व्यंजन' योजना की लॉचिंग की। कार्यक्रम में 05 विभूतियों विंग कमाण्डर शुभांशु शुक्ल, अलख पाण्डेय, रश्मि आर्य, डॉ0 हरिओम पंवार व डॉ0 सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच जनपदों (जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अम्बेडकरनगर, झांसी) के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये। इससे पूर्व, उन्होंने अन्य अतिथियों के साथ 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' थीम पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

आने वाले दिनों में यह प्रेरणा स्थल राष्ट्र चेतना की जागृति का स्थल बनेगा। जनसंघ की स्थापना करने वाले तथा कश्मीर के लिये अपना बलिदान देने वाले डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एकात्म मानववाद के जनक पं0 दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बना यह स्थल दशकों तक देश को दिशा प्रदान करेगा।

प्रदेश सरकार ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के माध्यम से कूड़े को कंचन में बदलने की व्यवस्था की है। यह समग्र उत्तर प्रदेश को प्रेरणा प्रदान करने वाला स्थान बना है। आज यहां पर सी0एम0 युवा उद्यमी विकास अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच जनपदों को सम्मानित किया गया है। इस अभियान में प्रत्येक वर्ष 01 लाख युवाओं को 05 लाख रुपये तक ब्याज व गारन्टी मुक्त ऋण देने तथा 10 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। अब तक 01 लाख 30 हजार युवाओं को 05 हजार 322 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हो चुका है।

गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार के घोषणा पत्र में 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना की कल्पना सम्मिलित की गयी। तब कुछ लोग कहते थे कि क्या यह उत्तर प्रदेश में सम्भव हो पाएगा। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यह योजना प्रदेश के साथ-साथ सम्पूर्ण देश में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। यह योजना कारीगरों, युवाओं, महिलाओं के लिये रोजगार का साधन बनी है। आज यहां पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से सम्बन्धित व्यंजन मेला लगा है। प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजनों को लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत करने का काम किया है।

गृह मंत्री जी ने कहा कि आज विंग कमाण्डर शुभांशु शुक्ला, श्री अलख पाण्डेय, सुश्री रश्मि आर्य, डॉ0 हरिओम पंवार तथा डॉ0 सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। इससे निश्चित रूप से कई प्रतिभाशाली युवाओं को अपने क्षेत्र में अच्छा

प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग डॉ0 हरिओम पंवार जी को लम्बे अरसे से सुन रहे हैं। इन्होंने सतर्कता व सटीकता के साथ अनेक प्रकार की कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया है।

आज यहां लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारम्भ हुआ है। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना की डिटेल प्लानिंग की गयी है। वर्ष 2025-26 में इसके प्रथम चरण में आज 06 जोन का शिलान्यास हुआ। वर्ष 2026-27 में द्वितीय चरण में 06 जोन का लोकार्पण और 30 जोन का शिलान्यास होगा। वर्ष 2027-28 में तृतीय चरण में 30 जोन का लोकार्पण और बचे हुए 39 जोन का शिलान्यास किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त होगा, जिससे वह अपने माता-पिता की सेवा भी कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में योजनाओं को धरातल पर उतारा है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज यह प्रदेश भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। डबल इंजन सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक-थ्रू राज्य बनाकर विकास को प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाया है। विगत 03 वर्षों में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 17 प्रतिशत रही है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत योगदान उत्तर प्रदेश का है। निःसंकोच कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट बन चुका है। यह प्रदेश गन्ना व इथेनॉल उत्पाद में देश में नम्बर 01 पर है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 'उत्तर प्रदेश दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुये कहा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी नयी पहचान बना रहा है। विगत 11 वर्षों में हमने बदलते हुये भारत की तस्वीर देखी है। 'उत्तर प्रदेश दिवस' के उपलक्ष्य में नये भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक सन्देश प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने सन्देश में लिखा है कि आज 24 जनवरी को 'उत्तर प्रदेश दिवस' मनाया जा रहा है। मैं सभी यू0पी0वासियों को 'उत्तर प्रदेश दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे चुनकर लोकसभा भेजा है। इसलिए यह दिन मेरे लिये और भी विशेष हो जाता है। यू0पी0 के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है, वह मेरे लिये बहुत बड़ी पूंजी है।

उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एम0एस0एम0ई0, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं, जैसे बनारसी साड़ियां, भदोही के कालीन, कन्नौज का इत्र या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन। यू0पी0 के हर जिले की अपनी शक्ति है। 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना ने यहां के लाखां लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही, सेमीकण्डक्टर चिप्स, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन तथा डिफेन्स कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकसित होते भारत का प्रतिबिम्ब बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश के नम्बर-1 होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश मजबूत कानून-व्यवस्था का उदाहरण बन चुका है। नये कीर्तिमान के साथ ही राज्य ने जनसेवा और लोककल्याणकारी नीतियों को अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में बने नये घरों से लेकर बेहतर जीवन के लिए उन तक पहुँच रही विभिन्न सुविधाएं अन्त्योदय के लिये सरकार के समर्पण को प्रदर्शित करती हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि प्रदेश पिछड़ों को प्राथमिकता के मंत्र को आत्मसात करते हुये आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है कि मैंने गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया था। आज यह योजना गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिये संकल्प का भी अवसर है। राज्य के सभी निवासियों को विकास के प्रत्येक पैरामीटर पर प्रदेश को नम्बर वन बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा।

प्रदेश के युवाओं के लिये सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेन्ट जोन नामक एक नयी योजना का शुभारम्भ भी किया गया है। यह एप्लॉयमेन्ट जोन प्रदेश के प्रत्येक जनपद में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किये जाएंगे। नौकरी करने अथवा अपना कारोबार प्रारम्भ करने के इच्छुक युवाओं के स्केल को स्किल डेवलपमेन्ट में बदलने का कार्य किया जायेगा। इसके पश्चात उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप उन्हें रोजगार से जोड़ा जायेगा। ■

भारत-ईयू के बीच व्यापारिक गठबंधन वैश्विक अर्थव्यवस्था को देगा दिशा

भारत और यूरोपीय संघ (India–EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के सफल निष्कर्ष पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक और अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। विश्व के प्रमुख मीडिया संस्थानों, यूरोपीय देशों के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, वैश्विक उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित नीति विशेषज्ञों ने इस समझौते को ऐतिहासिक, रणनीतिक और समयोचित बताते हुए इसकी सराहना की है। यह समझौता न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में भी इसे एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस समझौते के विशाल दायरे, महत्वाकांक्षा और रणनीतिक समय-निर्धारण को प्रमुखता से उजागर किया है। कई प्रमुख वैश्विक समाचार माध्यमों ने इसे "मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स" की संज्ञा देते हुए कहा है कि यह समझौता विश्व के सबसे बड़े आर्थिक समूह और सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था को एक साथ लाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस एफटीए के तहत दोनों पक्षों के बीच अधिकांश वस्तुओं पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की जाएगी, जिससे व्यापार, निवेश और आपूर्ति-श्रंखला एकीकरण को नई गति मिलेगी।

यूरोप के कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं ने इस समझौते का खुले तौर पर स्वागत किया है। उन्होंने इसे भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। यूरोपीय नेताओं ने यह भी कहा है कि यह समझौता विकास, समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगा तथा बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में दोनों पक्षों की भूमिका को और मजबूत करेगा। कुछ नेताओं ने इसके शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया है ताकि इसके लाभ आम नागरिकों, उद्योगों और छोटे एवं मध्यम उद्यमों तक पहुँच सकें। उद्योग जगत की प्रतिक्रिया भी अत्यंत उत्साहजनक रही है। भारत में सक्रिय यूरोपीय और वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने इस समझौते को लंबे समय से प्रतीक्षित उपलब्धि बताया है।

उनके अनुसार, यह एफ टी ए निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण, रक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल प्रौद्योगिकी और आपूर्ति-श्रंखला सहयोग के नए अवसर पैदा करेगा। उद्योग प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि यह समझौता नियम-आधारित वैश्विक व्यापार को मज़बूती देगा और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा।

वैश्विक नीति विशेषज्ञों और रणनीतिक मामलों के जानकारों ने भी भारत–ईयू एफटीए को सही समय पर किया गया एक ठोस और दूरदर्शी समझौता बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देगा तथा वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता और सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।

कुल मिलाकर, भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग, आपसी विश्वास और रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा।■

कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार किया

उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उ0प्र0 सहित 09 राज्यों के कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति देकर अपने-अपने प्रदेशों की लोक संस्कृति एवं पारम्परिक गीतों एवं संगीतों के माध्यम से उपस्थित समुदाय को भाव विभोर कर दिया। तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उ0प्र0 सहित 10 राज्यों के कलाकारों ने अपने प्रदेश की समृद्ध लोक विरासत परम्पराओं, मान्यताओं तथा आस्था का परिचय देते हुए यूपी दिवस को भव्य एवं अविस्मरणीय बना दिया। गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी को मा0 मुख्यमंत्री के शासकीय आवास पर आयोजित कलाकार सम्मान समारोह में जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं उ0प्र0 के कलाकारों से मा0 मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया और उ0प्र0 में आने का अनुभव की जानकारी ली।

संवाद के दौरान कलाकारों ने कहा उत्तर प्रदेश के विकास के विषय में सुना था आज विकास, विरासत और सम्मान से साक्षात्कार कर अभिभूत हैं। कलाकारों ने अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन का अनुरोध किया। इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों को अयोध्या धाम के दर्शन कराने के निर्देश दिए। सम्मान समारोह में सभी कलाकारों को ओडीओपी किट, प्रमाण पत्र आदि प्रदान कर मा0 मुख्यमंत्री जी ने सभी राज्यों के अतिथि कलाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने एक संदेश में कहा है कि तीन दिवसीय उ0प्र0 दिवस के दौरान शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विभिन्न राज्यों से पधारे कलाकारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोक कलाओं को जीवंत बनाने में लोक कलाकारों की अहम भूमिका है। ये कलाकार लोक संगीत के एम्बेस्डर भी है। आज बहुत सी लोक कलाएं बिलुप्त के कगार पर है। मा0 मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता एवं कलाकारों के प्रति संवदेनशीलता के चलते संस्कृति विभाग द्वारा उ0प्र0 लोक संगीत आदि विधाओं को जीवंत बनाने का कार्य किया जा रहा है।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से उ0प्र0 में ग्राम पंचायतों को वाद्ययंत्रों का सेट भी वितरित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी पारम्परिक लोकनृत्य, संगीत, नाटक एवं विभिन्न पर्वों पर गाये जाने वाले गीतों को पुनर्जीवित कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसके साथ ही निर्धन एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ये कलाकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। लोक संगीत को जीवित बनाये रखने में इनका योगदान अतुलनीय है।

समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव संस्कृति एवं पर्यटन अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, विषेश सचिव संस्कृति संजय कुमार सिंह, निदेशक सूचना एवं संस्कृति विशाल सिंह, जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी, अपर निदेशक संस्कृति श्रृष्टि धवन, सहायक निदेशक तुहिन दिवेदी, राजेश अहिरवार, रीनू रंग भारती सहित सूचना एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी उपास्थित रहे।■

77वां गणतंत्र दिवस उत्साह व गरिमा के साथ मनाया गया

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया गया। विधान भवन के सामने आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली।

गणतंत्र दिवस समारोह की आकर्षक परेड में सम्मिलित भारतीय सेना के आयुधां, मार्च पास्ट, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा झांकियों आदि ने दर्शकों का मन मोह लिया। परेड के मौके पर बी0एम0पी0-2 सारथ टैंक, 105 एम0एम0 लाइट फील्ड गन, लाइट स्ट्राइक व्हीकल, आर्मड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल तथा आल टेरेन व्हीकल (ए0टी0वी0) का प्रदर्शन किया गया। परेड के दौरान हैलीकॉप्टर द्वारा परेड स्थल पर पुष्प वर्षा भी की गयी।

गणतंत्र दिवस की परेड में 16 राजपूत रेजीमेन्ट (पुरुष टुकड़ी), जाट/सिख लाइट इन्फेन्ट्री (ब्रास बैण्ड), 6/11 गोरखा राइफल्स (पुरुष टुकड़ी), 6/11 प्लस 3/5 गोरखा राइफल्स (पाइप बैण्ड), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (पुरुष टुकड़ी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ब्रास बैण्ड), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (पुरुष टुकड़ी), ए0टी0एस0 कमाण्डो (पुरुष टुकड़ी), यू0पी0 पुलिस (पुरुष टुकड़ी), सशस्त्र सीमा बल (ब्रास बैण्ड), हरियाणा पुलिस (पुरुष टुकड़ी), उत्तर प्रदेश वन विभाग (पुरुष टुकड़ी), यू0पी0 होमगार्ड्स (पाइप बैण्ड), उत्तर प्रदेश वन विभाग (महिला टुकड़ी) ने प्रतिभाग किया।

परेड में पी0ए0सी0 32वीं वाहिनी (पुरुष टुकड़ी), पी0ए0सी0 32वीं वाहिनी (पाइप बैण्ड), पी0ए0सी0 35वीं वाहिनी (पुरुष टुकड़ी), पी0ए0सी0 35वीं वाहिनी (ब्रास बैण्ड), यू0पी0 होमगार्ड्स (पुरुष टुकड़ी), यू0पी0 होमगार्ड्स (ब्रास बैण्ड), यू0पी0 होमगार्ड्स (महिला टुकड़ी), प्रान्तीय रक्षक दल (पुरुष टुकड़ी), प्रान्तीय रक्षक दल (ब्रास बैण्ड), प्रान्तीय रक्षक दल (महिला टुकड़ी), एन0सी0सी0 (मार्च पास्ट बालक), एन0सी0सी0 (मार्च पास्ट बालिका) भी सम्मिलित हुईं।

इसके अलावा, बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल गर्ल्स इण्टर कॉलेज (ब्रास बैण्ड बालिका), कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय उ0प्र0 सैनिक स्कूल (ब्रास बैण्ड बालक), कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय उ0प्र0 सैनिक स्कूल (मार्च पास्ट मिश्रित), अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला (मार्च पास्ट बालिका), माध्यमिक विद्यालय जनभवन (ब्रास बैण्ड मिश्रित), कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, लखनऊ (मार्च पास्ट बालिका), नेशनल इण्टर कॉलेज लखनऊ (ब्रास बैण्ड मिश्रित), सेन्ट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड

लखनऊ (मार्च पास्ट बालक), सेन्ट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड (पाइप बैण्ड मिश्रित), सेन्ट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम् लखनऊ (मार्च पास्ट बालिका), सेन्ट जोसेफ कॉलेज रुचि खण्ड लखनऊ (ब्रास बैण्ड मिश्रित), एस0आर0 ग्लोबल स्कूल बक्शी का तालाब लखनऊ (मार्च पास्ट मिश्रित), एस0आर0 ग्लोबल स्कूल बक्शी का तालाब लखनऊ (पाइप बैण्ड बालिका), राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज शाहमीना रोड (मार्च पास्ट बालिका), राजकीय जुबिली इण्टर कॉलेज (ब्रास बैण्ड बालक) फ्लैग मार्च में शामिल हुए।

साथ ही, महर्षि विद्या मन्दिर आई0आई0एम0 रोड (मार्च पास्ट बालिका), महर्षि विद्या मन्दिर आई0आई0एम0 रोड (पाइप बैण्ड बालक), सिटी मॉण्टेसरी स्कूल, अलीगंज प्रथम शाखा (मार्च पास्ट बालिका), सिटी मॉण्टेसरी स्कूल, गोमती नगर प्रथम शाखा (पाइप बैण्ड मिश्रित), बाल विद्या मन्दिर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल चारबाग (मार्च पास्ट बालक), श्री जय नारायण मिश्र इण्टर कॉलेज, चारबाग (ब्रास बैण्ड बालक), लखनऊ पब्लिक कॉलेज सेक्टर-ई, आम्रपाली योजना (मार्च पास्ट बालक), लखनऊ पब्लिक कॉलेज ए ब्लॉक राजाजीपुरम (ब्रास बैण्ड मिश्रित), लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट जानकीपुरम (मार्च पास्ट बालिका) ने फ्लैग मार्च में प्रतिभाग किया।

इसके अलावा, उम्मीद संस्था लखनऊ (ब्रास बैण्ड मिश्रित), बाल निकुंज इण्टर कॉलेज मोहिबुल्लापुर (मार्च पास्ट बालक), सरस्वती विद्या मन्दिर सेक्टर-क्यू, अलीगंज (ब्रास बैण्ड मिश्रित), ब्वॉयज ऐंग्लो बंगाली इण्टर कॉलेज सुन्दरबाग (मार्च पास्ट बालक), सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार (मार्च पास्ट मिश्रित), सिटी मॉण्टेसरी स्कूल कानपुर रोड (ब्रास बैण्ड मिश्रित), ए0पी0एस0 एकेडमी सेनानी बिहार रायबरेली रोड (मार्च पास्ट मिश्रित), श्रीराम एकेडमी सीतापुर रोड (ब्रास बैण्ड मिश्रित), भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश लखनऊ (फ्लैग मार्च मिश्रित), लखनऊ पब्लिक कॉलेज विनम्र खण्ड गोमतीनगर (पाइप बैण्ड बालिका), लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर-9 वृन्दावन योजना (फ्लैग मार्च बालिका), सेन्ट क्लेयर कॉन्वेंट स्कूल (ब्रास बैण्ड मिश्रित), सिटी मॉण्टेसरी स्कूल इन्दिरा नगर प्रथम शाखा (फ्लैग मार्च बालक), सिटी मॉण्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम शाखा (पाइप बैण्ड मिश्रित) तथा सिटी मॉण्टेसरी स्कूल आर0डी0एस0ओ0 (फ्लैग मार्च बालिका) फ्लैग मार्च में सम्मिलित हुए।

विभिन्न विद्यालयां के छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता पर आधारित आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। सेण्ट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम द्वारा 'अवध की धूल चन्दन है नृत्य', लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट जानकीपुरम द्वारा 'नया हिन्दुस्तान नयी कीर्ति नृत्य', बाल विद्या मन्दिर चारबाग द्वारा 'उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नृत्य', एस0आर0 ग्लोबल बक्शी का तालाब द्वारा 'नारी शक्ति नृत्य', सिटी मॉण्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम शाखा द्वारा 'सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत नृत्य', बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल पलटन छावनी द्वारा 'विकसित भारत विकसित प्रदेश ड्रिल' तथा उम्मीद संस्था लखनऊ द्वारा 'तिरंगा नृत्य' प्रस्तुत किये गये।

इस अवसर पर संस्कृति विभाग की सांस्कृतिक प्रस्तुति 'विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश' के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के बधाई, महाराष्ट्र के लेजियम, जम्मू कश्मीर के राउफ, सिक्किम के तमांग सेलो, गुजरात के तलवार रास के साथ ही, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपूरा, अरुणाचल प्रदेश के लोकनृत्य जैसे-पैट्रियोटिक व बिजू नृत्य, सिंग्फो, निसी को लोक कलाकारों ने प्रस्तुत किया। प्रदेश के कलाकारां द्वारा शंख वादन, डमरु वादन, बधावा, मयूर व ढेढ़िया तथा भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया।■

राजनीति का चश्मा तुष्टिकरण से हटकर सांस्कृतिक गौरव की ओर

देश और विदेश में अब सनातन की शक्ति को लोग मानने और स्वीकारने लगे हैं। देश की राजनीति में एक दौर ऐसा भी रहा जब मंदिर में प्रवेश करने और मूर्ति पूजा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से परहेज करते थे जबकि अन्य धर्म के कार्यक्रमों में राजनीति दल जाने से परहेज नहीं करते थे लेकिन अब समय बदल रहा है। मोदी और योगी ने देश-विदेश में इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि सनातन ही सबसे श्रेष्ठ है। खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक कई जगहों में हाल फिलहाल चरमपंथियों की कई घटनाओं से सनातन के प्रति लोगों के मन में लगाव बढ़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मंदिर और मठ में पूजा अर्चना, विभिन्न पर्व में गंगा स्नान किया जाना और सनातन के पर्व व त्योहार को सार्वजनिक रूप से जनता के बीच मनाने लोगों की आस्था बढ़ी है। इस सनातन श्रेष्ठ को विपक्षी दलों ने भी स्वीकार किया है। कांग्रेस के भी दिग्गज नेता मंदिरों के चैखट में अब जाने से परहेज न करते है। उन्हें इस बात का भय नहीं सताता है कि उनका कोर वोट कहीं छिटक न जाए।

सीएम योगी आयोध्या, काशी, मथुरा के मंदिरों में पूर्जा-अर्चना कार्यक्रमों में शामिल होकर सनातन श्रेष्ठ जयघोश को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इस साल की शुरूआत में सीएम ने काशी में जाकर बाबा विष्वनाथ जी की पूजा अर्चना की और आम जन को संदेश दिया कि सभी अपने धर्म और संस्कृति के अनुरूप ही अपने आचरण को ढाले। अयोध्या, काशी और मथुरा के जरिए सरकरा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और

सॉफ्ट पावर से स्पिरिचुअल पावर तक

अबू धाबी में मंदिररू कभी अकल्पनीय लगने वाली बात अब सच है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश में बीएपीएस हिंदू मंदिर का निर्माण और पीएम मोदी द्वारा उसका उद्घाटन सनातन की वैश्विक स्वीकार्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यूरोप और अन्य देशों में बढ़ते कट्टरपंथ के बीच, सनातन धर्म की श्वसुधैव कुटुंबकमश् (विश्व एक परिवार है) और सर्वे भवंतु सुखिनश् की भावना को दुनिया शांति के एक स्थायी विकल्प के रूप में देख रही है।

काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब मथुरा-वृंदावन के विकास और कृष्ण जन्मभूमि की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जा रही है।
राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए सनातनी कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिससे यूपी को वैश्विक सनातन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। सरकार ने पूर्वांचल के उपेक्षित और प्राचीन मंदिरों, जैसे महर्षि भृगु (बलिया) और ऋषि दुर्वासा (आजमगढ़) के आश्रमों के जीर्णोद्धार के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सरकार द्वारा 11 प्राचीन किलों और इमारतों (जैसे झांसी का टहरौली किला और ललितपुर का तालबेहट किला) को पीपीपी मॉडल के तहत विरासत होटलों और सांस्कृतिक केंद्रों में बदला जा रहा है। मंदिर के पुजारियों के कल्याण के लिए एक समर्पित बोर्ड का गठन किया गया है और पुराने मंदिरों के रखरखाव के लिए नई नीति लागू की गई है। 2024 में उत्तर प्रदेश में 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जो सनातन आधारित बुनियादी ढांचे के विकास का परिणाम है। धार्मिक स्थलों के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को अपने घरों को गेस्ट हाउस में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे रोजगार और सनातन संस्कृति का प्रचार एक साथ हो सके। आध्यात्मिक महत्व के स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 4,560 करोड़ रूपए का निवेश किया जा रहा है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को सनातन धर्म के वैश्विक प्रतिनिधि कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दीपोत्सव (अयोध्या), रंगोत्सव (मथुरा) और देव दीपावली (वाराणसी) जैसे आयोजनों को राजकीय संरक्षण देकर उन्हें वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया गया है। मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, जो भारतीय समाज में गाय के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को प्रदर्शित करेगा। सीएम योगी ने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए संस्कृत को अभिव्यक्ति का जीवंत माध्यम बनाने पर जोर दिया है ■

सोमनाथ अटूट आस्था के 1000 वर्ष (1026-2026) :मोदी

सोमनाथ... ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में, प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है..."सौराष्ट्रे सोमनाथं च...यानि ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है:

अर्थात्, सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है।

दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था।
वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था।
सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय-समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुन:निर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण सम्पन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे।
1026 में एक हजार वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण, वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। हर पंक्ति में क्रूरता के निशान मिलते हैं, ये ऐसा दु:ख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है।■

दावोस में टीम योगी की बड़ी उपलब्धि

तीन लाख करोड़ के मिले निवेश प्रस्ताव

स्विट्जरलैंड के दावोस में 19 से 23 जनवरी तक आयोजित 56 वें विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) की वार्षिक बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए लगभग 3 लाख करोड़ (2.92 करोड़ से अधिक) के निवेश प्रस्ताव (एमओयू) सुनिश्चित किए हैं। सम्मेलन से लौटने के बाद प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उत्तर प्रदेश की भागीदारी और निवेश उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इस उपलब्धि को प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने वाला बताया।

वित्त मंत्री ने बताया कि सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 119 उच्च स्तरीय बैठकें कीं, जिनमें 55-56 प्रमुख वैश्विक कंपनियां शामिल रहीं। इन बैठकों के परिणामस्वरूप डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, वेस्ट-टू-एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ईवी, फार्मा, हेल्थकेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में 31 एमओयू संपन्न हुए। इन सभी एमओयू के माध्यम से कुल प्रस्तावित निवेश 2.92 लाख करोड़ रूपए से अधिक का है, जो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।

वित्त मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव नीदरलैंड की कंपनी एएम-ग्रीन' के साथ हुआ है। इस एमओयू के तहत ग्रेटर नोएडा में एआई आधारित 1 गीगावॉट डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से वर्ष 2028 तक लगभग 2.10 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इस परियोजना से न केवल प्रदेश में डिजिटल और तकनीकी क्रांति आएगी, बल्कि इससे जुड़े सहायक उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा। इसके साथ ही, एएसआर टेक्नोलॉजी के साथ 200 करोड़ का एमओयू भी हुआ। वहीं, उबर द्वारा विस्तारित मोबिलिटी सहभागिता और संभावित जीसीसी की स्थापना में रुचि व्यक्त की गई।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एमओयू किए गए

यूपीनेडा के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दावोस सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एमओयू किए गए, जिनमें सोलर रूफटॉप एवं बैटरी एनर्जी स्टोरेज में 1000 करोड़, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट में 1100 करोड़, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एवं सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में 10,500 करोड़, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पार्क (3 गीगावॉट सोलर सेल मॉड्यूल ◌ 60 मेगावॉट सोलर प्लांट) में 3800 करोड़ का एमओयू सम्मिलित है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा एवं ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर गैर-वित्तीय एमओयू तथा आरईसी लिमिटेड द्वारा 500 मेगावाट कृषि अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 8000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव शामिल रहे।

उद्योग, स्टील और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा निवेश

वित्त मंत्री ने बताया कि रश्मि मेटालिक्स ने 1 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए 4000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही एबी इनबेव, गोदरेज, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों के साथ स्मार्ट फैक्ट्री, इंडस्ट्री 4.0 और सप्लाई चेन विकास

को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। यही नहीं, डुपोंट, रामको ग्रुप और श्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ जल प्रबंधन, सिंचाई, सीवेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन, माइक्रोग्रिड और स्मार्ट बिल्डिंग्स पर साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डुपोंट ने उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000-60,000 रुपये प्रति सोलर यूनिट की संभावनाओं सहित झांसी और लखनऊ, नोएडा व वाराणसी में पायलट परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा।

प्रौद्योगिकी, फार्मा कंपनियों के साथ व्यापक चर्चा

वहीं, गूगल, उबर, एएसआर टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, सिस्को, डेलॉइट, गूगल क्लाउड, ऑटोनेशन एनर्जी और एसएस टेक्नोलॉजी सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ व्यापक चर्चा हुई। इन चर्चाओं में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी), एआई, डेटा सेंटर, डिजिटल गवर्नेंस, कौशल विकास और मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर फोकस रहा। दूसरी तरफ, हेल्थकेयर, फार्मा और लाइफ साइंसेज में भी निवेश पर चर्चा हुई। बायर कंज्यूमर हेल्थ और एजीएलटट टेक्नोलॉजीज ने एग्रो-प्रोसेसिंग, फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, अनुसंधान एवं विकास तथा जीवन विज्ञान क्षेत्रों में अवसरों पर विचार-विमर्श किया। बायर कंज्यूमर हेल्थ द्वारा राज्य के औद्योगिक केंद्रों में विस्तार की संभावनाओं को रेखांकित किया गया।

निवेश धरातल पर उतारने के लिए बनेगी सिंगल-विंडो टीम

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया कि दावोस में हुए सभी एमओयू की नियमित मॉनिटरिंग और फॉलो-अप किया जाएगा। इन

31 निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित सिंगल-विंडो टीम गठित की जाएगी, जो स्वीकृतियों से लेकर परियोजनाओं के संचालन तक समयबद्ध सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकसित भारत /2047 के विजन को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेकर राज्य की विकास क्षमता, निवेश अनुकूल वातावरण और मजबूत शासन प्रणाली का प्रभावी प्रदर्शन किया। इस भागीदारी ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूती दी। उन्होंने बताया कि "संवाद की भावना" विषय पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, वैश्विक उद्योग जगत के शीर्ष नेतृत्व, नीति-निर्माता, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और नवप्रवर्तक शामिल रहे। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सम्मेलन में सहभागिता की। भारत के 10 राज्यों ने इस मंच पर अपनी भागीदारी दर्ज कराई, जिनमें उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा।

साइबर सुरक्षा, एमएसएमई और ओडीओपी से मजबूत अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी ने निवेशकों का भरोसा जीता है। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में केवल 2 साइबर थाने थे, जबकि अब सभी जनपदों में साइबर थाने स्थापित हो चुके हैं। एमएसएमई और ओडीओपी योजनाओं के चलते उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच गया है और प्रदेश के उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। इस अवसर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गई टीम यूपी के सभी सदस्य मौजूद रहे। इनमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अमित सिंह, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद और डायरेक्टर यूपीनेडा इंद्रजीत सिंह शामिल रहे।■

बंगाल में उभरते हिन्दू स्वरों में बदलते राजनीतिक समीकरण

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल इन दिनों धार्मिक और राजनीतिक उफान का केंद्र बना हुआ है। बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक समूहों की सक्रियता के बीच हिन्दू धर्मगुरुओं एवं संगठनों की मोर्चाबंदी ने क्या हिंदू क्रांति का शंखनाद किया है? क्या यह आगामी विधानसभा चुनावों में हिंदू वोटों को एकत्र करने का नया एजेंडा है, या पश्चिम बंगाल में लगातार हिन्दुओं पर हो रहे हमलों, उनको कुचलने की कुचेष्टाओं एवं मुस्लिम तुष्टीकरण का माकुल जबाव है। बाबा बागेश्वर धाम-धीरेन्द्र शास्त्री सहित अनेक हिंदू धर्मगुरुओं के प्रवचनीय हस्तक्षेप, लाखों लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ और संतों की हुंकार से एक नई चेतना आकार लेती दिखाई दे रही है। यह उभार महज आस्था का नहीं, बल्कि पहचान, सुरक्षा और गौरव के भावों का उभार है।पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाना मानो एक सोए हुए राक्षस को जगाने जैसा है, क्योंकि यह केवल एक मस्जिद का प्रश्न नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द की कसौटी है। सदियों से चला आ रहा बाबरी विवाद भारत की सामाजिक चेतना पर गहरे जख्म छोड़ चुका है-जिसने राजनीति को उग्र बनाया, समुदायों को बाँटा और नफरत व हिंसा के बीज बोए। ऐसे समय में जब राष्ट्र विभिन्न संकटों से जूझ रहा है, इस विवाद को नए भूगोल में स्थानांतरित कर हवा देना सामाजिक सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है।

सद्भाव और शांति की बुनियाद पर खड़े भारत को ऐसे मुद्दों की आवश्यकता है जो एकता को मजबूत करें, न कि पुराने घाव कुरेदकर समाज में तनाव और अविश्वास पैदा करें। अतः आवश्यक है कि नेतृत्व इस संवेदनशील विषय को विवेक, संवाद और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर संभाले, ताकि भारत का बहुलतावादी चरित्र और साझा सभ्यता सुरक्षित रह सके।निश्चित ही बाबरी मस्जिद विवाद को हवा देकर कुछ मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक वर्गों ने तनाव का वातावरण खड़ा किया है। इन दो समानांतर धाराओं की टकराहट ने बंगाल को विमर्श के केंद्र में ला दिया है कि क्या राज्य में हिंदू संगठित होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हिन्दू-विरोधी साजिशों एवं षडयंत्रों का अंत चाहते हैं? बंगाल परंपरा से बौद्धिक और सांस्कृतिक बहुलता का प्रदेश रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में हिंदू सामाजिक मानस में एक बदलाव दिख रहा है। "गजवा हिंद" के प्रलापों के प्रतिकार में "भगवा हिंद" का संकल्प उभर रहा है। पांच लाख से अधिक हिंदुओं द्वारा एक साथ गीता पाठ करना इसी उभार का संकेत है, जिसमें धर्म प्रदर्शन शक्ति और अस्मिता के रूप में सामने आता है। साध्वी ऋतंभरा के वक्तव्यों ने इस उभार को एक नया स्वर दिया है। उनका स्पष्ट कथन कि "यह धरती प्रभु श्रीराम की है और श्रीराम की ही रहेगी" बंगाल सहित पूरे देश के हिंदू मानस में गूंज रहा है। यह कथन सिर्फ

आस्था की घोषणा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अधिकार और आधिपत्य की अनुभूति का उद्घोष है। उनके भाषणों में उभरती चेतावनी है कि यदि हिंदू अपनी संस्कृति, परंपरा और मंदिरों की रक्षा के लिए नहीं उठे तो इतिहास स्वयं उनसे जवाब मांगेगा। इस पृष्ठभूमि में बाबरी विवाद का पुनर्स्मरण राजनीति का साधन भी प्रतीत होता है। मुस्लिम संगठनों द्वारा इसकी मांगों को आगे बढ़ाना और नेताओं द्वारा इसे मुद्दा बनाना निश्चित ही सामाजिक भावना को चुनौती देता है। इसका प्रतिउत्तर धार्मिक मंचों से आया है, जहां प्रवचनों और सभाओं ने इसे हिंदू गौरव और अस्तित्व के प्रश्न के रूप में चित्रित किया है। ऐसे में यह कहना असंगत नहीं कि बंगाल की जमीन पर हिंदू पहचान की राजनीति तेजी से आकार ले रही है और हिन्दू धर्मगुरुओं के स्वर इसे वैचारिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उनका यह कथन कि "राम का नाम अनंत है, पर पुरुषार्थ के बिना सिर्फ नाम से रामराज्य नहीं आएगा" एक सीधा संकेत है कि हिंदू समाज को संगठित, सक्रिय और आत्मनिर्भर होना होगा। इस व्यापक परिदृश्य का मुख्य केंद्रबिंदु राजनीति है। क्या यह सब आगामी विधानसभा चुनावों का संकेत है?

बंगाल की राजनीति लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका के आसपास घूमती रही है और ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के भरोसे को अपने समर्थन की नींव बनाया है। परंतु यदि हिंदू मतदाता नए सांस्कृतिक उभार से प्रेरित होकर एकजुट होते हैं, तो पहली बार बंगाल की सत्ता-समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा और संघ परिवार का प्रयास भी इसी दिशा में है कि धार्मिक सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना का मंच बनाकर हिंदू अस्मिता को वैचारिक शक्ति प्रदान करना। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और धार्मिक प्रवचनीय हस्तक्षेपों द्वारा बंगाल में हिंदू एकता और पहचान को जागृत करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इस राजनीतिक परिपाटी में बाबा बागेश्वर जैसे मंच प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, धर्म-सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना की पाठशाला में बदला जा रहा है। साध्वी ऋतंभरा का बंगाल में सक्रिय होना उसी रणनीति की कड़ी है, क्योंकि उनका सशक्त भाषण हिंदू भावनाओं को

झकझोरता है। बंगाल जिसकी पहचान बौद्धिक विनम्रता, कविता, महात्म्य और सहिष्णुता से जुड़ी रही है, वह अब टकराव, ध्रूवीकरण और प्रतिआक्रामकता की ओर बढ़ता दिख रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में भावनात्मक आवेश बढ़ रहा है और नेताओं द्वारा इस माहौल को चुनावी लाभ के लिए साधने की त्रासद कोशिशें तेज हैं। यह परिस्थिति बंगाल के सामाजिक ताने-बाने के लिए चुनौतीपूर्ण है। फिर भी एक बात निर्विवाद है-बंगाल में एक नई चेतना, एक नई आकांक्षा जन्म ले रही है।

यह पूर्ण क्रांति है या क्रांति का शंखनाद, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, परन्तु प्रारंभिक संकेत स्पष्ट हैं। हिंदू पहचान की राजनीति बंगाल में निर्णायक होती जा रही है, मुस्लिम वोट-बैंक की राजनीति पहली बार चुनौती में दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी की सत्ता को सांस्कृतिक विरोध का नया मोर्चा मिला है। अब यह समय बताएगा कि यह उभार सत्ता बदलता है या सामाजिक संवाद को बदलता है। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब केवल विकास, योजनाओं और नेतृत्व की नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और प्रभुत्व की राजनीति बन चुकी है। यही कारण है कि धार्मिक मंचों की आवाजें चुनावी मैदान की धड़कन बन रही हैं।

बंगाल अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ा है-जहाँ राम का दावा और राम की भूमि का संकल्प राजनीति, समाज और भविष्य तीनों को प्रभावित करने वाला तत्व बन चुका है। न केवल मुस्लिम तुष्टिकरण बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी एवं तानाशाही का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रक्रिया बन गयी है। ममता वोट बैंक की राजनीति के लिये कानून की धज्जियां बार-बार उड़ाती रही है। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलामानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्लादेशियों का या अब बाबरी मस्जिद का। इसके लिए ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है, कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। तृणमूल कांग्रेस हिन्दुओं को पश्चिम बंगाल में सेकेंड क्लास सिटिजन एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की उसकी सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलकती रही है। ममता ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। बदले हुए राजनीतिक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वह महज 'बागेश्वर बनाम बाबरी विवाद' नहीं है, यह सांस्कृतिक-धार्मिक पुनर्स्थापन की कोशिश बनाम राजनीतिक मुस्लिम केंद्रवाद की प्रतिस्पर्धा है। अभी के लिए, बंगाल की जमीन पर धर्म, राजनीति और पहचान का नया त्रिकोण उभर चुका है और वही आने वाले समय में बंगाल की राजनीतिक दिशा, सामाजिक संबंधों और सत्ता के समीकरणों को आकार देगा। ■

भारत मे फैला सुरंग परियोजना का जाल

साल 2024 में, भारत ने कोलकाता में अपनी पहली अंडरवॉटर मेट्रो सुरंग के शुभारंभ के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जो हुगली नदी के नीचे एस्प्लेनाड और हावड़ा मैदान को जोड़ती है। यह इंजीनियरिंग उपलब्धि न केवल देश की बढ़ती तकनीकी और अवसंरचनात्मक क्षमताओं को दर्शाती है बल्कि भारत के सबसे व्यस्त महानगरीय क्षेत्रों में शहरी आवागमन की नई परिभाषा भी प्रस्तुत करती है। सुरंगों की नई पीढ़ी आकार लेने को तैयार है। ये आगामी परियोजनाएँ देश में आवागमन और संपर्क के तरीके को नया रूप देने का वादा करती हैं। निम्नलिखित आने वाली परियोजनाएँ प्रगति के पैमाने को उजागर करती हैं।

जोजिला सुरंग

जोजिला सुरंग भारत की अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभर रही है, जो कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण हिमालयी चट्टानों को भेदते हुए लद्दाख और देश के अन्य हिस्सों के बीच एक भरोसेमंद, सभी मौसमों में चालू रहने वाला संपर्क स्थापित करती है। लगभग 12 किलोमीटर पहले ही पूरा हो चुका है, और इस परियोजना में उन्नत सुरक्षा उपाय और एक सेमी-ट्रांस्वर्स वेंटिलेशन सिस्टम शामिल है, जो पर्वतों के अंदर स्थिर वायु प्रवाह बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। परियोजना में स्मार्ट सुरंग (एससीएडीए) प्रणाली शामिल है, जिसे नई ऑस्ट्रियाई सुरंग निर्माण विधि (एनएटीएम) का उपयोग करके निर्मित किया गया है। इसमें सीसीटीवी निगरानी, रेडियो नियंत्रण, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और वेंटिलेशन सिस्टम जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस परियोजना में आधुनिक तकनीक के उपयोग के चलते सरकार की

> *कुल 213 कि.मी. की परियोजना में से 199 कि.मी. सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। इस परियोजना की एक प्रमुख तकनीकी उपलब्धि यह है कि भारतीय रेलवे में पहली बार हिमालयी भूविज्ञान में सुरंग खोदने वाली मशीन (टीबीएम) का उपयोग किया गया।*

5,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई है। पूरी हो जाने पर यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग बन जाएगी, जिससे इसका राष्ट्रीय महत्व और भी बढ़ जाएगा। 11,578 फीट की ऊँचाई पर स्थित और 30 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली यह परियोजना 2028 तक पूर्ण होने के लिए तैयार है। श्रीनगर-कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, यह क्षेत्र में नागरिक और सैन्य गतिशीलता, दोनों को बढ़ावा देने का वादा करती है।

मुंबई-अहमदाबाद उच्च-गति रेल सुरंग

भारत का मुंबई-अहमदाबाद उच्च-गति रेल गलियारा अपनी 4.8 किमी लंबी जलमग्न सुरंग खंड में सफलता प्राप्त कर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग ले चुका है। यह देश के पहले बुलेट ट्रेन मार्ग की प्रमुख विशेषता को परिभाषित करता है।

घन्सोली और शिलफाटा, दोनों सिरों से एक साथ खोदी गई इस सुरंग ने असाधारण चुनौतियाँ पेश कीं। सटीकता के साथ मिलने से पहले टीमों ने कठिन जलमग्न भूभाग को पार किया, जिसे भारत के अभियांत्रिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सराहा गया। परियोजना में उन्नत नई ऑस्ट्रियाई सुरंग निर्माण विधि (एनएटीएम) का उपयोग किया गया है, जिसे व्यापक सुरक्षा उपायों से समर्थित किया गया है। यह सुरंग एकल-ट्यूब तकनीक के साथ डिजाइन की गई है, जिसमें दो उच्च-गति ट्रेनें समा सकती हैं, और यह अत्याधुनिक रेल निर्माण में अग्रणी है तथा भारत की अगली पीढ़ी की परिवहन अवसंरचना में नवाचार को दर्शाती है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना की सुरंगें

उत्तराखंड में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन भारतीय हिमालय में एक महत्वपूर्ण सुरंग निर्माण परियोजना है। लगभग 125 किमी लंबी इस रेल लाइन का मार्ग भूवैज्ञानिक रूप से कुछ सबसे जटिल और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिसके कारण यह परियोजना मुख्य रूप से सुरंग-आधारित है। इसमें 16 मुख्य लाइन सुरंगें शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 105 किमी है, और 12 समानांतर आपातकालीन सुरंगें हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 98 कि.मी. है। कुल 213 कि.मी. की परियोजना में से 199 कि.मी. सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। इस परियोजना की एक प्रमुख तकनीकी उपलब्धि यह है कि भारतीय रेलवे में पहली बार हिमालयी भूविज्ञान में सुरंग खोदने वाली मशीन (टीबीएम) का उपयोग किया गया। यह 14.8 कि.मी. लंबी टी-8 सुरंग के लिए प्रयुक्त हुई, जहाँ एक सफल ब्रेकथ्रू हासिल किया गया। उन्नत सुरंग निर्माण तकनीकें और सतत् निगरानी प्रणालियां अपनाई गई, जिससे सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। यह ऋषिकेश-कर्णप्रयाग सुरंगों को भारत में उच्च-ऊँचाई वाली रेलवे सुरंग निर्माण का एक प्रेरक उदाहरण बनाती हैं।

अंधेरे में रोशनी की एक किरण

भारत की सुरंग अवसंरचना स्मार्ट और अधिक सुदृढ़ विकास की दिशा में स्पष्ट परिवर्तन को दर्शाती है। ये परियोजनाएँ कनेक्टिविटी की लंबे समय से मौजूद चुनौतियों का समाधान करती हैं। साथ ही आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन भी करती हैं। प्रौद्योगिकी और निर्माण में हुई प्रगति ने जटिल भूभाग में सुरक्षित निर्माण करने की भारत की क्षमता को मजबूत किया है। जैसे-जैसे नई सुरंगें परिचालन में आती जाएंगी, वे आवाजाही, विश्वसनीयता और क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार जारी रखेंगी। ये सभी मिलकर एक ऐसे भविष्य का संकेत देते हैं, जहाँ भौगोलिक स्थितियाँ अब प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकतीं।■

विश्व आर्थिक मंच 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश संभावनाओं का किया प्रदर्शन, बड़े निवेश प्रस्ताव किए सुनिश्चित

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज लोकभवन में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने स्विट्ज़रलैंड के दावोस-क्लोस्टर्स में 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित 56वें विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2026 में लगातार तीसरे वर्ष प्रतिभागिता के माध्यम से राज्य की विकास यात्रा और निवेश क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इस प्रतिभागिता से आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान करने एवं उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की राज्य की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित हुई। "संवाद की भावना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के लगभग 3,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, उद्योग जगत का नेतृत्व, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और नवाचारकर्ता शामिल थे।

भारत सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में श्री प्रह्लाद जोशी, माननीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री के साथ-साथ उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। "पार्टनर विद भारत" के संदेश को दृढ़ता से प्रतिबिंबित करते हुए, इंडिया पैविलियन दावोस के प्रोमेनेड-63 पर रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया था। यह पैविलियन भारत की निवेश गाथा, आर्थिक परिवर्तन और प्रौद्योगिकीय अवसरों का केंद्रीय मंच रहा, जिसने भारत को वैश्विक साझेदारियों के लिए एक एकीकृत और निवेश हेतु तैयार बाजार के रूप में प्रस्तुत किया। इंडिया पैविलियन की एक प्रमुख विशेषता दस भारतीय राज्यों की सामूहिक भागीदारी रही, जिन्होंने भारत को एक एकीकृत निवेश बाजार के रूप में प्रस्तुत करते हुए ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और अवस्थापना जैसे क्षेत्रों में विविध अवसरों का प्रदर्शन किया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में दावोस पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल में श्री दीपक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त; श्री अमित सिंह, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय; श्री विजय किरन आनंद, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी; तथा श्री इंदरजीत सिंह, निदेशक, यूपीनेडा सहित इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी शामिल थे।
प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल द्वारा वैश्विक नेतृत्व, नीति-निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ 119 बैठकों के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट-से-ऊर्जा (वेस्ट-टू-इनर्जी), विनिर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 31 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका कुल प्रस्तावित निवेश ₹2.92

लाख करोड़ से अधिक है। ये साझेदारियाँ राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विज़न के अनुरूप हैं।

गूगल, उबर, एचसीएलटेक, टेक महिंद्रा, सिस्को, डेलॉइट, गूगल क्लाउड, ऑटोमेशन एनीवेयर और एसए टेक्नोलॉजीज सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ व्यापक चर्चाएँ हुईं। इनमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स डेटा सेंटर, डिजिटल गवर्नेंस, कौशल विकास और मोबिलिटी सोल्यूशन्स पर फोकस रहा। प्रमुख उपलब्धियों में एसए टेक्नोलॉजीज के साथ ₹200 करोड़ का डवन् और एएम ग्रीन ग्रुप के साथ ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट। प्-केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु ऐतिहासिक डवन् शामिल है, जिसमें वर्ष 2028 तक लगभग ₹2.1 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। उबर द्वारा भी विस्तारित मोबिलिटी सहभागिता और नोएडा में संभावित की स्थापना में रुचि व्यक्त की।

राज्य ने हरित विकास एजेंडा के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएँ सुनिश्चित कीं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक गैर-वित्तीय डवन् पर हस्ताक्षर किए। आरईसी लिमिटेड ने 500 मेगावाट की कृषि अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹8,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया। कार्बन कंपास और रेनर्जी डायनेमिक्स द्वारा एवं नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्यों के अनुरूप ब्रिकेटिंग और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों के विकास हेतु राज्य के साथ साझेदारी के अंतर्गत चक्रीय-अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनोमी), ग्रामीण आय और स्वच्छ मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीनको और एस्सार ग्रुप के साथ संवाद ने ऊर्जा परिवर्तन पाइपलाइन को और मजबूत किया। उत्तर प्रदेश ने धातु, औद्योगिक स्वचालन और कंज्यूमर गुड्ज़ के क्षेत्रों में विनिर्माण हेतु वृहद निवेश आकर्षित किए। रश्मि मेटालर्जिकल ने एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए ₹4,000 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की प्रतिबद्धता जताई। एबी इनबेफ, गोदरेज, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, क्यूब्लर ग्रुप, नाइडर इलेक्ट्रिक और रश्मि ग्रुप ने विनिर्माण विस्तार, स्मार्ट फैक्ट्रियों, इंडस्ट्री 4.0 और आपूर्ति श्रृंखला विकास की संभावनाओं पर चर्चा की।

ग्रुंडफोस, रामकी ग्रुप और नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी वैश्विक स्तर की कंपनियों के साथ जल प्रबंधन, सिंचाई, सोलर पंप समाधान, सीवेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन, माइक्रोग्रिड और स्मार्ट विलेज पर

साझेदारी पर चर्चा हुई। ग्रुंडफोस ने उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 50,000-60,000 पंपों के सोलराइजेशन की संभावनाएँ चिन्हित कीं और लखनऊ, नोएडा व वाराणसी में पायलट परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा।

बायर कंज्यूमर हेल्थ और एगिलेंट टेक्नोलॉजीज ने एग्रो-प्रोसेसिंग, फार्मा, डायग्नॉस्टिक्स, अनुसंधान एवं विकास तथा जीवन विज्ञान क्षेत्रों में अवसरों पर विचार-विमर्श किया। बायर द्वारा राज्य के औद्योगिक केंद्रों में विस्तार की संभावनाएँ रेखांकित कीं, जबकि एगिलेंट ने नवाचार-आधारित विकास हेतु प्रयोगशाला, बायोटेक और अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने पर बल दिया।

ब्लैकरॉक, डेलॉइट, मार्श मैकलेनन, कमबबव और वेल्थ डोर के साथ दीर्घकालिक पूंजी निवेश, संस्थागत क्षमता निर्माण, जोखिम प्रबंधन, कौशल विकास और वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता पर चर्चा हुई। कमबबव ने उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील सेवा क्षेत्र व रोज़गार इकोसिस्टम के दृष्टिगत लखनऊ में केंद्र स्थापित करने में रुचि दिखाई।

प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी कानपुर एवं एमआईटी के पूर्व छात्र तथा नासा के पूर्व वैज्ञानिक, कार्बन कंपास के संस्थापक एवं सीईओ श्री नीरज अग्रवाल के साथ भी जलवायु नवाचार और धारणीयता से जुड़े भविष्य-उन्मुख अवसरों पर संवाद किया।

भविष्य की कार्ययोजना

विश्व आर्थिक मंच, दावोस में हुए सार्थक संवादों के आधार पर, इन्वेस्ट यूपी द्वारा निवेश आशयों को धरातल पर उतारने के लिए नीतिगत समर्थन, अवसंरचना, कुशल मानव संसाधन, नियामकीय सुविधा और अंतर-विभागीय समन्वय को और सुदृढ़ व सुविधायुक्त बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार सभी हस्ताक्षरित की नियमित निगरानी और फॉलो-अप सुनिश्चित करेगी।

उक्त 31 निवेश प्रस्तावों के लिए एक समर्पित सिंगल-विंडो टीम गठित की जाएगी, जो स्वीकृतियों से लेकर क्रियान्वयन तक समग्र सहयोग प्रदान करेगी। इस संस्थागत दृष्टिकोण के माध्यम से उत्तर प्रदेश, विकसित भारत / 2047 के विजन के अनुरूप, सतत विकास, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रगति को गति देते हुए एक भरोसेमंद और भविष्य-तैयार निवेश गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। ■

अगले चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी बसपा अपने दम पर बनाएंगे सरकार: मायावती

उत्तर प्रदेश मेंबहु जन समाज पार्टी करीब 15 सालों से सत्ता से बाहर है 2007 से 2012 तक सत्ता में रही बसपा को पिछले तीन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है इस दौरान तीन लोकसभा चुनाव में भी बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे मेंयह धारणा आम तौर पर बनने लगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का कालखंड खत्म हो चुका है ऐसा इस लिये भी कहा जा रहा था क्योंकि मायावती ने चुनाव प्रचार से भी काफी हद तक किनारा कर लिया था।बात अंतिम बार 2007 में विधानसभा चुनाव जीती बसपा की उस समय की चुनावी रणनीति की की जाये तो 2007 का चुनाव मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से जीती थी। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने राजनीतिक इतिहास रच दिया। 2007 में मायावती नेसामाजिक समीकरण साधकर 403 सीटों में से 206 सीटों पर कब्जा जमाया और कुल 30.43 प्रतिशत वोट हासिल किए। बसपा सुप्रीमो की यह जीत दलितों के परंपरागत वोट बैंक के अलावा ब्राह्मणों और कुछ गैर-यादव पिछड़ी जातियों तथा मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से संभव हुई थी। यह और बात है कि इसके बाद मायावती का यह फार्मूला दोबारा परवान नहीं चढ़ पाया।

बहरहाल, अबकी करीब 20 सालों के बाद एक बार फिर 2027 के विधानसभा चनाव के लिये बसपा के पक्ष में दलितों के साथ ब्राह्मणों एवं मुसलमानों के वोटों की गोलबंदी देखी जा रही है ब्राह्मणों और मुसलमानों के एक बार फिर बसपा की तरफ रुख करने की वजह में जाया जाए तो ऐसा लगता है कि योगी राज में ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनके साथ यह सरकार नाइंसाफी कर रही है नौकरशाही से लेकर सरकार तक में महत्वपूर्ण पदों से ब्राह्मणों को दूर रखा गया है यही वजह है कि पिछले कुछ समय में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में ब्राह्मण नेताओं का प्रवेश अधिक देखा गया हैजनवरी 2026 में अंबेडकर नगर से भाजपा के दिग्गज नेता राधेश्याम पांडे 51-100 ब्राह्मण समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हुए। उन्होंने मायावती से मुलाकात कर पार्टी जॉइन की। दिसंबर 2025 में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता जैसे जितेंद्र मिश्रा, दीपक द्विवेदी,

नीरज पांडे, विशाल मिश्रा, वैभव दुबे, अनुराग शुक्ला, मोहित शर्मा भाजपा से बसपा में शामिल हुए। यह 2027 चुनाव से पहले भाजपा को झटका था। जनवरी 2026 में एक अन्य बड़े ब्राह्मण नेता ने मायावती से मुलाकात कर बसपा जॉइन की।

वहीं मुसलमान इसलिये बसपा की तरफ फिर से मुड़ता दिख रहा है क्योंकि उसे लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों से वोट तो लेती है, लेकिन उनका (मुसलमानों का) हक उन्हें नहीं दिया जाता है। इसी तरह से मुसीबत के समय भी अखिलेश मुसलमानों से दूरी बना लेते हैं।पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को अकेला छोड़ दना इसकी सबसे बड़ी मिसाल बताते हैं। बाहु बली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की भी मौत के लिये मुस्लिम समाज कहीं न कहीं अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते हैं।उन्हें लगता है कि विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अतीक और मुख्तार को लेकर उकसाया नहीं होता तो आज वह जिंदा होते।दलित वोटरों ने बसपा को पूर्ण समर्थन दिया। जाटव समुदाय के 86 प्रतिशत मतदाताओं ने मायावती को चना, जबकि वाल्मीकि जाति के 71 प्रतिशत ने पार्टी को तरजीह दी। पासी समुदाय से 53 प्रतिशत और अन्य अनुसूचित जातियों से 58 प्रतिशत वोट बसपा के खाते मेंआए। इन दलित उपजातियों की मजबूत पकड़ ने पार्टी को आधार प्रदान किया, क्योंकि दलित उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 21 प्रतिशत हैं। ऊपरी जातियों में ब्राह्मणों का 16 प्रतिशत समर्थन मिला, जो निर्णायक साबित हुआ। बसपा ने 51 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 20 जीते, लेकिन यह जीत मुख्यतः निचली जातियों के वोटों से आई। ठाकुरों और अन्य ऊपरी जातियों ने भी सीमित लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पिछड़ी जातियों ने भी बसपा की ओर रुख किया। गैर-यादव और गैर-कुर्मी अन्य पिछड़ा वर्ग के30 प्रतिशत मतदाताओं ने पार्टी चुनी। कुल पिछड़ा वर्ग के कई खंडों से वोट उमड़े, जिसने सामाजिक समीकरण को मजबूत बनाया। बसपा ने 110 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार मदैान में उतारे। यह समर्थन समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से छिटके वोटरों का परिणाम था, जो विकास और सुशासन के वादों से प्रभावित हुए।मुस्लिम मतदाताओं का योगदान सबसे चमत्कारिक रहा। 2007 में बसपा को कुल वोटों में मुस्लिम वोट 10 प्रतिशत से अधिक थे। एक सर्वे केअनुसार 17 प्रतिशत मुस्लिमों ने पार्टी को समर्थन दिया। पार्टी ने 61 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 29 विधायक बने। उत्तर प्रदेश मेंमुस्लिम आबादी 19 प्रतिशत होने केबावजूद यह समर्थन बहुमत के लिए जरूरी साबित हुआ। समाजवादी पार्टी से नाराज मुस्लिमों ने बसपा को मौका दिया, क्योंकि मायावती ने अल्पसंख्यक कल्याण के वादे किए। मायावती की रणनीति ने जातिगत बंधनों को तोड़ा। दलित-ब्राह्मण गठजोड़ की बात भले ही प्रचारित हुई, लेकिन वास्तव में जाटव, वाल्मीकि, पासी जैसे दलितों के साथ अन्य अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग के30 प्रतिशत, ब्राह्मणों के 16 प्रतिशत और मुस्लिमों के 17 प्रतिशत वोटों ने चमत्कार रचा। बसपा का वोट प्रतिशत 2002 के 23 से बढ़कर 30 हो गया। पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों से ऊपरी जातियों को लुभाया, जबकि मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया। यह जीत सामाजिक न्याय की मिसाल बनी।मायावती ने सत्ता में आकर अपराध पर अंकुश लगाया और विकास कार्य तेज किए। लेकिन जातिगत समीकरण की बारीकी ने राजनीति को नया आयाम दिया। दलितों का कोर वोट 80-86 प्रतिशत तक रहा, ऊपरी जातियों से 16-20 उम्मीदवार जीते, पिछड़ों से 30 प्रतिशत समर्थन और मुस्लिमों के 17 प्रतिशत ने पूर्ण बहुमत सुनिश्चित किया।

बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरह से पंडित कार्ड खेल रही हैं, इसका ताजा उदाहरण यह बताता है कि उनका ब्राह्मणों के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है। मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों को लेकर सवर्णों, विशेषकर ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद से चल रही राजनीति पर और इसके बाद बॉलीवुड फिल्म 'घूसखोर पंडित' के खिलाफ ब्राह्मणों के पक्ष में बयान दने मेंदरी नहीं की। इससे पहले यूजीसी के नये नियम पर संयमित प्रतिक्रिया दते हुए मायावती ने कहा था कि इस नये कानून से किसी को बिना वजह प्रताड़ित नहीं किया जाये। देश भर में 'घूसखोर पंडित' फिल्म के विरोध के बीच बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। वहीं यूजीसी प्रकरण में असहज हु ई भाजपा भी अब फिल्म के मुद्दे पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म पर एफआईआर के निर्देश देकर इस वर्ग केसाथ का संदेश दिया।

बसपा प्रमुख ने इस मामले में06 फरवरी को एक्स पर लिखा, 'यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अक्ेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी 'पंडित' को घुसपैठिया बताकर पूरे देश मेंजो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस जातिसूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, यह बसपा की मांग है।'वर्ष 2007 में बसपा ने ब्राह्मणों के साथ सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला था और बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार भी बसपा उसी फार्मूले पर चुनावी तैयारी में जुटी है और पार्टी प्रमुख के एक्स पोस्ट को उसी रणनीति को आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है। ■

विधानसभाओं की कार्यवाही के लिए निश्चित-पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन को सम्म्बोधित करते हुवे चाहे जिस भी राजनीतिक दल से आते हो, उनका आचरण दलगत राजनीति से हटकर पूर्णतः न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष होना चाहिए तथा न्यायपूर्ण व निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।

अपने संबोधन में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधायिका के माध्यम से जनता की आकांक्षाएं और आवाज़ शासन तक पहुँचती है, तथा उनका समाधान होता है। ऐसे में राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही का घटता समय सभी के लिए चिंताजनक है। श्री बिरला ने राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के लिए निश्चित एवं पर्याप्त समय सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि सदन जितना अधिक चलेगा, उतनी ही अधिक सार्थक, गंभीर और परिणामोन्मुख चर्चा संभव होगी।

बिरला ने कहा कि आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के युग में जनप्रतिनिधियों के प्रत्येक आचरण पर जनता की दृष्टि रहती है, इसलिए संसदीय शिष्टाचार और अनुशासन का पालन और भी अधिक आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि आज तकनीक के युग में जब चारों तरफ़ से सूचना का प्रवाह होता है, तब सदन की प्रामाणिकता बनाए रखना, हम सभी की महती ज़िम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जैसे मंच लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ाते हैं, आपसी समन्वय को मजबूत करते हैं और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाते हैं। इन सम्मेलनों से देशभर में नीतियों और कल्याणकारी उपायों में सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता मिलती है।

बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि सदन में सभी सदस्यों, विशेषकर नए और युवा सदस्यों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि विधानमंडल जनता की समस्याओं को उठाने का सबसे प्रभावी मंच बना रहे।

यह चौथी बार है जब उत्तर प्रदेश इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इससे पूर्व राज्य में दिसंबर 1961, अक्तूबर 1985 तथा जनवरी–फरवरी 2015 में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है।

विधायिका लोकतंत्र का सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण स्तंभ

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश

महाना ने कहा कि विधायिका लोकतंत्र का सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण स्तंभ है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों का विशेष महत्व है। असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता है।

इन्हीं विचार-विमर्शों और मतभेदों के माध्यम से जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का निर्माण होता है। महाना अखिल भारतीय 86वें पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों के 62 वें सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी पांच वर्षों के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस दल के अधिक विधायक होते हैं, उसी दल का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन विधायिका की वास्तविक शक्ति जनता के हितों की रक्षा और जनकल्याण की भावना में निहित होती है।उन्होंने कहा कि वर्ष 1921 से प्रारंभ हुए ऐसे सम्मेलनों ने भारतीय लोकतंत्र को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सम्मेलनों के माध्यम से विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय मर्यादाओं और जनहित से जुड़े विषयों पर निरंतर गंभीर एवं सार्थक विमर्श होता रहा है। इस सम्मेलन में भी देश भर से आए पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने कहा कि पिछले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही केवल दो बार स्थगित हुई है, जो सदन की सशक्त कार्यसंस्कृति, अनुशासन और सकारात्मक वातावरण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा दिए गए आलोचनात्मक सुझावों को भी पूरी गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि सदन के सभी सदस्यों का लक्ष्य एक ही है—प्रदेश की जनता का कल्याण।श्री महाना ने कहा कि इस सम्मेलन में आप सभी की उपस्थिति से उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि और कार्यसंस्कृति पूरे देश में जाएगी। आप सभी यहां से उत्तर प्रदेश के सकारात्मक, विकसित और सशक्त स्वरूप का अनुभव लेकर जाएंगे। आपके आगमन से सम्मेलन की गरिमा और आभा में वृद्धि हुई है। इसके लिए उन्होंने सभी सम्मानित अतिथियों, प्रतिनिधियों एवं प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि यह अधिवेशन अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को 'फ्रंट रनर' राज्य के रूप में चिन्हित किया जाना प्रदेश की प्रगति का स्पष्ट प्रमाण है। प्रदेश की राजस्व वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और विजन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 36 घंटे तक कार्यवाही का सफल संचालन लोकतांत्रिक परंपराओं और कार्यकुशलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।श्री हरिवंश नारायण सिंह ने शिक्षा, कानून-व्यवस्था और विद्युत क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाल के वर्षों में अनेक सकारात्मक और ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। आधुनिकता और पारंपरिक संसदीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित उत्तर प्रदेश विधानसभा तकनीक के माध्यम से कार्य संचालन में गति, पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनाए हुए है। कार्य संचालन नियमावली में किए गए सुधार, डिजिटल व्यवस्थाओं का उपयोग तथा विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना द्वारा प्रत्येक सदस्य से किया जाने वाला सीधा संवाद एक सराहनीय एवं अनुकरणीय पहल है, जिससे सदन की कार्यक्षमता और गरिमा दोनों में वृद्धि हुई है.■

सही दिशा, भरोसे-समावेशन के साथ एआई स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ा सकता है

सूबे के सीएमयोगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत ने एआई को जिम्मेदारी व मजबूती के साथ अपनाया है। इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने में भारत एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। सही दिशा, भरोसे और समावेशन के साथ एआई स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सटीक और न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तकनीक संवेदना से जुड़ती है, नीति नवाचार से संचालित होती है और शासन विश्वास पर आधारित होता है तो विकास समावेशी बनता है और भविष्य सुरक्षित होता है।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश एआई एण्ड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में एआई इम्पैक्ट समिट-2026 कार्यक्रम के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश एआई इन हेल्थ केयर से सम्बन्धित इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहा है। हमें हेल्थ केयर में एआई का उपयोग करके इस प्रकार कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना होगा, ताकि इस तकनीक का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को प्राप्त हो सके। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए लगभग 2 हजार करोड़ रुपये के यूपी एआई मिशन को अगले तीन वर्षों में फेज वाइज आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई हमारे लिए सुविधा है। यह हमारे कार्यों को आसान बनाएगा और एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा, लेकिन कोई भी तकनीक मानव द्वारा संचालित हो, किन्तु मानव उसके द्वारा संचालित न हो। आज उत्तर प्रदेश एआई, सेमीकण्डक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से तकनीक का प्रमुख केन्द्र बनकर उभरा है। एआई का उपयोग हेल्थ केयर के साथ ही एग्रीकल्चर, एजुकेशन इत्यादि क्षेत्रों में भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई का इस्तेमाल रीएक्टिव के स्थान पर प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में दक्षता के साथ ही बीमारियों का पूर्वानुमान, उसके पैटर्न की पहचान तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एआई के बेहतर उपयोग की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पेशेंट की केस स्टडी के डाटा को सुरक्षित करने, उसका विश्लेषण व उपयोग करने के साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में स्पेसिफिक बीमारी से जुड़े मामलों पर फोकस्ड कार्यवाही में भी एआई का सदुपयोग किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में वैश्विक शोध, नवाचार और निवेश का अग्रणी केन्द्र बनने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज होना एक चौलेंज था। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में निजी और गवर्नमेन्ट स्तर पर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित थे। आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं तथा 2 एम्स संचालित हो रहे हैं। कोविड-19 के समय प्रदेश में 36 जनपद ऐसे थे, जहाँ आईसीयू का एक बेड नहीं था। वहाँ डिजिटल एक्स-रे, कलर डॉप्लर, ब्लड बैंक, डायलिसिस तथा ऑक्सीजन प्लाण्ट की व्यवस्था नहीं थी। क्रिटिकल केयर के लिए कोई बेहतर व्यवस्था प्रदेश में लखनऊ के अलावा अन्य जनपदों में नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कोविड कालखण्ड में भारत सरकार के सहयोग से 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। कोविड कालखण्ड में वर्चुअल आईसीयू सफलतापूर्वक प्रदेश में संचालित किये गये। लखनऊ के 3 महत्वपूर्ण हेल्थ केयर सेन्टर एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया गया। प्रत्येक जनपद तथा क्रिटिकल केयर के

चिकित्सकों को यहां पर ट्रेंड किया गया। मास्टर ट्रेनर तैयार किये गयें। प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों ने जनपद की टीम को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के अन्य कार्यक्रम भी चलाये गये। आज इस प्रकार की सुविधाएं प्रत्येक जनपद में मौजूद हैं। प्रत्येक जनपद में डायलिसिस, ब्लड बैंक, कलर डॉप्लर की सुविधाएं दी जा रही हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीकन्सल्टेंसी की व्यवस्था को ध्और बेहतर किया जा सकता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने प्रारम्भ किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रत्येक वर्ष 1200-1500 बच्चों की इन्सेफेलाइटिस से मृत्यु होती थी। उसे नियंत्रित करना कठिन था। इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाते थे। आज उसी प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु जीरो है। हमने एक फोकस्ड कार्यवाही के तहत इसे पूरी तरह समाप्त व उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त की। हमने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में सुधार किया है। अब यू0पी0 बॉटम में नहीं, नेशनल एवरेज के समकक्ष है। प्रदेश में संस्थागत प्रसव में भी सुधार हुआ है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरुप अनेक नेशनल प्रोग्राम प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

टीबी मुक्त भारत के लिए प्रदेश में टीबी नियंत्रण के लिए एआई टूल के माध्यम से टीबी रोगियों की पहचान की जा रही है। यह टूल टीबी रोगियों की पहचान करने तथा कमजोर मोहल्लों को इण्डिकेट करने में मदद करेगा। यदि एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए सभी डाटा को एकत्र करें तथा प्रोएक्टिव एप्रोच के साथ आगे बढ़ें तो अनेक वेक्टरजनित बीमारियों को महामारी के रूप में संकट बनने से पूर्व उपचारित तथा नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार डाटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय, बेहतर नीति और बेहतर परिणाम को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। डबल इंजन सरकार आज डबल स्पीड से स्केल से स्किल और स्किल से स्पीड तक की यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के युवाओं की स्किलिंग के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज, सैमसंग के साथ उन्नत स्किलिंग कार्यक्रम प्रारम्भ किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश इस दिशा में एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स विकसित हो रहे हैं। प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है, विगत 11 वर्षों में भारत में लोगों ने धरातल पर मूर्त रूप लेते हुए देखा है। वर्ष 2017 से पूर्व जनता की ओर से सबसे ज्यादा शिकायतें राशन न मिलने की आती थीं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा प्रश्न किये जाते थे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अनियमितताओं को तकनीक का इस्तेमाल करके दूर किया गया। प्रदेश में 80 हजार दुकानों के लिए ई-पॉस मशीन लगवायी गयीं। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। परिणामस्वरूप आज शिकायत लगभग जीरो हो गयी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के विश्वास को अर्जित करने और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए तथा व्यक्तिगत जीवन में, टेक्नोलॉजी कैसे परिवर्तन ला सकती है, इसका यह एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हम सबके सामने हैं। पहले शासन द्वारा निराश्रित महिला, वृद्धजन तथा दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत 300 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसमें बहुत अनियमितताएं व भ्रष्टाचार था। वर्तमान में डीबीटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख लाभार्थियां को प्रतिमाह 1,000 रुपये पेंशन के रूप प्रदान किये जा रहे हैं। प्रत्येक तीसरे माह इन लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उनके अकाउण्ट में पैसा भेजा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनधन अकाउण्ट तथा डिजिटल ट्रान्जैक्शन ने पूरी प्रक्रिया को सरल बना दिया है। प्रत्येक लाभार्थी को शत-प्रतिशत लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है, इसका एक उदाहरण है। अर्थात तकनीक काम को आसान कर देती है तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंचाती है। इससे जब अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति मजबूत होता है, तब विकासपरक योजनाएं तेजी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। इन नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति भी है। हम साफ नीयत के साथ आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश में एक संवेदनशील, समयबद्ध, जवाबदेह और तकनीक आधारित स्वास्थ्य मॉडल देने में सफल हुए। राज्य सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया है, फिर भी कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। कुछ अच्छा करने की अपेक्षाएं तथा आकांक्षाएं प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।■

जोश से भरी टीम

भारत क्रिकेट टीम में कई दिलचस्प

तमाम अटकलों और आशंकाओं के बीच आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत की जीत के साथ 7 फरवरी से शुरू हो गया। भारत और श्रीलंका दोनों मेजबान है। यह लोकप्रिय टूर्नामेंट 8 मार्च तक चलेगा। इसमें बीस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीमें खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे बड़े पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। टूर्नामेंट का येह 10वां संस्करण, 2024 टी20 विश्व कप के समान प्रारूप के हिसाब से खेला जाएगा, जिसमें आठ स्थानों पर 55 रोमांचक मैच होंगे। इनमें पांच भारत में और तीन श्रीलंका में होंगे।

बदली-बदली सी टीम इंडिया

इस फार्मेट में मौजूदा चैंपियन भारत है। भारत पुरुष टी20 विश्व कप इतिहास में दो खिताबों के साथ सबसे सफल मुल्क है। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड भी दो बार के चैंपियन हैं। हालांकि, इस बार सह-मेजबान टीम में भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल नहीं हैं, क्योंकि दोनों ने 2024 में भारत की खिताब जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के लाडले और देश के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को उनके खराब टी20 फॉर्म के कारण भारत की टी20 विश्व कप 2026 टीम से बाहर कर दिया गया। 14 मैचों में उनका औसत 24.63 रहा था। वैसे भी टीम संयोजन में भी वह फिट नहीं बैठ रहे थे। आखिरकार सूर्यकुमार यादव को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। दिलचस्प है कि इस विश्व कप में हिस्सा लेने वाले 15 क्रिकेटरों में से नौ खिलाड़ी गुजरात, ***मद्रास, मुंबई और पंजाब*** के पारंपरिक क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन यूपी, बिहार, रांची और कर्नाटक जैसे गैर परांपरागत क्षेत्रों के लड़कों ने भी अपनी मेहनत के बल पर टीम टी20 वर्ल्डकप में जगह बनाई।

भारत क्रिकेट टीम में कई दिलचस्प नाम है। टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, मुहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। सबके चयन के अपनी-अपनी वजहे हैं। सबने मेहनत की अपने खेल से टीम में जगह बनाई। मसलन बिहार के ईशान किशन को ले लें। ईशान को क्रिकेटर बनने का सपना तब पूरा करने के लिए अपने जन्मस्थान पटना से पड़ोसी राज्य झारखंड की टीम में शामिल होना पड़ा। अपना खेल दिखा कर वह टीम इंडिया में शामिल जरूर हो गए

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह आईपीएल में खेलने वाले अलीगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं। वे 2018-19 रणजी ट्रॉफी में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, जहां वे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।

लेकिन खास जगह नहीं बना पाए। वह 2023 के बाद से ड्रॉप चल रहे थे। हालांकि ईशान 2016 से आईपीएल खेल थे। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बल्ले से आग उगलने के बाद उनकी किस्मत चमकी। उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में जगह मिली। तिरुवनंतपुरम में भारत ने टी-20 में अपना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रन बनाए। इसमें ओपनर के रूप में ईशान किशन ने कमाल किया था। ईशान ने सिर्फ 42 गेंदों में शानदार शतक लगाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव गेंदों के लिहाज से टी-20 में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड में उन्हें जगह मिलनी तय हो गई। कीवी टीम के खिलाफ खेली गई सीरीज में भी उनका बल्ला जमकर बोला। उन्होंने अपना टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक जड़ा और पहले ही मैच में उन्होंने अपनी सार्थकता साबित कर दी।

नौजवानों के भरोसे

वरुण चक्रवर्ती की कहानी इससे भी दिलचस्प है। चौंकिए नहीं, वरुण चक्रवर्ती बंगाली नहीं हैं, उनका जन्म कर्नाटक के बीदर में हुआ था, उनके पिता तमिल-मल्याली मूल के हैं और माता कन्नड़ भाषी हैं। वरुण चक्रवर्ती एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज के रूप में खेलते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आर्किटेक्चर और फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया। डेढ़ साल तक उन्होंने एक आर्किटेक्चर कंपनी में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के रूप में काम किया। उनकी शुरुआत लगभग 14000 रुपये से हुई थी। क्रिकेट में शुरुआत अच्छी हुई फिर उन्हें जल्द लगने लगा वह लंबी रेस का घोड़ा नहीं हैं। वह संन्यास का मन बना चुके थे। लेकिन कुछ फोन कॉल्स ने उन्हें एक मौका दिया और तमिलनाडु प्रीमियर लीग (टीएनपीएल) में कुछ ओवर खेलने से उनकी जिंदगी बदल गई। वरुण चक्रवर्ती ने 2025 में शानदार फॉर्म दिखाते हुए टी20 इंटरनेशनल में 32 मैचों में 50 से अधिक विकेट ले लिए हैं, जिसमें 17 रन देकर 5 विकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 32वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की। आईपीएल में, वरुण ने 83 मैचों में 100 विकेट लिए हैं, जो उन्हें संयुक्त रूप से सबसे तेज स्पिनर बनाता है। कुछ एक को छोड़ दें तो नई टीम के सभी खिलाड़ियों की कहानी कुछ इसी तरह की है। अजीब से नाम वाले वाशिंगटन सुंदर एक प्रतिभाशाली भारतीय ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कई उपलब्धियां हासिल की, जिसमें 2021 में ऑस्ट्रेलिया में यादगार टेस्ट डेब्यू, निदाहस ट्रॉफी (2018) में बेहतरीन प्रदर्शन और आईपीएल में शानदार रिकॉर्ड शामिल हैं। वह 18 साल की उम्र में टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने थे। लेकिन इनके सितारे गर्दिश में आ गए। 2024 तक लोग उन्हें भूलने लगे थे। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 की घरेलू टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी हुई। भारत की ओर से उन्होंने सबसे ज़्यादा 16 विकेट लिए। 2025 में उन्होंने लॉर्ड्स में 4-22 के आंकड़े के साथ 51 वर्षों में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। उनके अंतरराष्ट्रीय करियर के 17 टेस्ट में 36 विकेट लेकर उन्होंने 885 रन बनाए। 29 वनडे में 29 विकेट लिए। और 58 टी20 में 51 विकेट झटके।

यूपी के रिंकू का जलवा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह आईपीएल में खेलने वाले अलीगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं। वे 2018-19 रणजी ट्रॉफी में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, जहां वे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। सिंह ने उत्तर प्रदेश, पंजाब किंग्स, सर्विसेज, कोलकाता नाइट राइडर्स, रेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया ए और सेंट्रल जोन सहित कई घरेलू और आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेला है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। मैदान पर उनके आक्रामक स्वभाव के कारण उन्हें 'रिंकू' उपनाम मिला है। 28 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की। यह फुर्तीला खिलाड़ी मैदान पर हर तरफ नजर आया, चौके बचाए और कई बेहतरीन कैच भी पकड़े। अजिंक्य रहाणे के बाद वह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में चार कैच पकड़ने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए। रिंकू का पहला कैच न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे का था, जिन्होंने 44 रन बनाए थे। कॉनवे को पहली पारी के नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 30 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए। हालांकि भारतीय टीम ये मैच 50 रनों से हार गई, लेकिन रिंकू का बल्ले और फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छे संकेत हैं।

सबकी निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर है। 2023 में टी20 टीम के कप्तान के रूप में उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 'हर किसी के पास अलग-अलग कौशल होते हैं, और वह मैदान पर आकर खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसलिए मैदान पर उतरने पर उन्हें यह आजादी देना बहुत जरूरी है, और मैं यही आजादी देने की कोशिश करता हूं।' बहरहाल ये आजादी इन्जवाय करने का वक्त है। भारत और श्रीलंका के मैदान में इन सबकी परीक्षा होगी।■

किशोरावस्था बदलाव का दौर, जिज्ञासाओं को शांत करना जरूरी

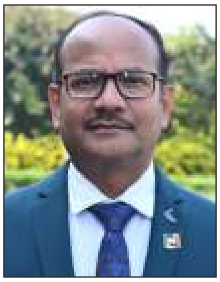

मुकेश शर्मा (एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर)
पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता दिवस पर विशेष
खुलकर अपनों से बात करें और समस्या का उचित समाधान पाएं

देश की आधी आबादी यानि महिलाओं और खासकर किशोर-किशोरियों (10 से 19 वर्ष) को पूरी तरह से स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का समुचित लाभ उठाने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं और किशोर-किशोरियां आगे भी आ रही हैं किन्तु कुछ भ्रांतियों के चलते आज भी कई बीमारियों या रोगों के बारे में वह खुलकर बात करने से अपनों तक से कतराते हैं या झिझक महसूस करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल है यौन जनित रोग (संक्रमण), जिसके बारे में वह अपनों से भी बात करने से हिचकते हैं। इस बारे में जागरूकता लाने और भ्रांतियों को जड़ से मिटाने के लिए ही हर साल 12 फरवरी को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है।

किशोरावस्था शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों का दौर होता है, ऐसे में देश के इन कर्णधारों को सही दिशा दिखाने के लिए भी आज का यह खास दिन बहुत मायने रखता है। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सुनी-सुनाई बातों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों के भरोसे किशोर-किशोरियों को छोड़ने से बेहतर है कि उनसे खुलकर बात करें और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें ताकि उनके सुनहरे भविष्य का रास्ता तैयार हो सके। इसी उद्देश्य से स्कूलों में किशोर/किशोरियों की काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाती है। किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक और साथिया केंद्र किशोरावस्था के बारे में सही जानकारी देने के साथ ही स्वास्थ्य समस्याओं का निदान भी करते हैं। इसके अलावा निकटतम सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों, आशा, एएनएम और घर के निकट स्थित आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) पर तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की भी ऐसे में मदद ली जा सकती है।

इस दिवस का मूल मकसद किशोर-किशोरियों और महिलाओं को यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी समुचित जानकारी मुहैया कराना है। गर्भ निरोधक साधनों के फायदे समझाने के साथ ही परिवार नियोजन के बारे में जागरूक बनाना है ताकि महिलाएं खुद से निर्णय लेने में सक्षम बन सकें कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए। यौन संचरित संक्रमण (एसटीआई) एक बड़ी समस्या है किन्तु लोग इस मुद्दे पर बात करने से कतराते हैं, जिसका असर किशोर-किशोरियों और दम्पति के प्रजनन स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को केवल शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है बल्कि उसे मानसिक और सामाजिक सरोकारों से भी जोड़कर देखने की आवश्यकता है। इसके लिए सुरक्षित गर्भनिरोधक विधियों के बारे में शिक्षित करने के साथ ही यौन संचरित संक्रमण और एचआईवी की रोकथाम और उनके लक्षणों और बचाव के बारे में भी समझ को विकसित करने की जरूरत है। इसके अलावा गर्भ न ठहरना या बच्चा न होने की समस्या को लेकर भी लोगों की भ्रांतियों को दूर किया जाना चाहिए और इस बारे में अपने साथी से खुलकर बात करनी चाहिए। सर्वाइकल और कैंसर की स्क्रीनिंग 30 वर्ष और उससे ऊपर की महिलाओं का अवश्य हो ताकि इस गंभीर बीमारी से आधी आबादी को आसानी से बचाया जा सके। इसमें जरूरी टीकाकरण की भी अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही यौन हिंसा और भेदभाव जैसी स्थितियों से उबारकर किशोर-किशोरियों और महिलाओं को शारीरिक, मानसिक स्वस्थ्य प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी आज का यह खास दिन हम सभी को प्रेरित करता है।

आज के समय में तमाम गर्भनिरोधक साधनों की मौजूदगी के बाद भी अनचाहा गर्भ धारण करना और असुरक्षित गर्भपात की स्थितियां इस ओर साफ़ इशारा करती हैं कि अभी इस मुद्दे पर समुदाय को जागरूक बनाने की सख्त जरूरत है। इसकी शुरुआत घर के बड़े-बुजुर्गों से होनी चाहिए ताकि वह अपनी आने वाली पीढ़ी को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बता सकें और संकोच व झिझक से बाहर निकलकर इस गंभीर मुद्दे पर बात करने में सहज महसूस कर सकें। महिलाओं को रजोनिवृत्ति (मेनोपाज) से होने वाले शारीरिक बदलावों और दिक्कतों आदि के बारे में भी शिक्षित किया जाना चाहिए। ■

triangle

Digital Platform Engineering
Design and development of scalable software platforms, enterprise systems, and integrated digital architectures

Web & Digital Experience Engineering
Development of corporate websites, web applications, and user-centric digital interfaces

Mobile Application Engineering
Design and development of native and cross-platform mobile applications

Business Technology Enablement for SMEs
Technology solutions addressing core operational needs such as CRM, e-commerce, billing, integrations, and workflow automation

Technology Strategy & Advisory
Consulting services relating to digital transformation, system architecture, and technology road-mapping

www.trianglemind.in

आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के

सभी वरिष्ठ नागरिकों

को मिल रहा वय वंदना योजना का लाभ

योजना की विशेषताएं

- सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार
- मौजूदा बीमारियों का कवरेज पहले दिन से लागू
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, जिनके पास पहले से कोई निजी बीमा है, वे भी पात्र होंगे
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के राज्य बीमा योजना (ESIC) के लाभार्थी भी पात्र होंगे

कैसे बनवाएं आयुष्मान वय वंदना कार्ड?

प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें → मोबाइल नंबर से लॉगिन करें → सभी आवश्यक जानकारी भरें और e-KYC करें → अपना कार्ड डाउनलोड करें

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर

पात्रता के मापदंड

लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है

आयु का सत्यापन आधार e-KYC के माध्यम से ही पूरा होगा

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत

15 जनवरी से 15 अप्रैल, 2026 तक विशेष अभियान

इस दौरान अपने नजदीकी कैंप पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं

सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची जानने के लिए QR कोड स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : 1800-1800-4444/14555

कार्यालय का पता: दूसरी और चौथी मंजिल, नवचेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

अब इंतजार किस बात का,
आज ही ऐप डाउनलोड कर बनवाएं

आयुष्मान वय वंदना कार्ड

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP